लखनऊ

हिंदी दैनिक

आर्यावर्त क्रांति

रविवार, 13 जुलाई, 2025
वर्ष : 10 । अंक: 356
मूल्य : 1 रुपये
पृष्ठ : 8

UPHIN/2014/57034

मित्र क्या है? एक आत्मा जो दो शरीरों में निवास करती है। - अरस्तू

TODAY WEATHER

DAY 37° Hi | NIGHT 26° Low

भारतीय न्याय व्यवस्था में सुधार की सख्त जरूरत, मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई का बड़ा बयान

भारतीय न्याय व्यवस्था अनोखी चुनौतियों का सामना कर रही

नई दिल्ली, एजेंसी। भारत के मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई ने शनिवार को कहा कि भारतीय न्याय व्यवस्था अनोखी चुनौतियों का सामना कर रही है और इसमें सुधार की सख्त ज़रूरत है। हैदराबाद के जस्टिस सिटी स्थित नालसार यूनिवर्सिटी ऑफ़ लॉ के दीक्षांत समारोह में न्यायमूर्ति गवई ने छात्रों को सलाह दी कि वे छात्रवृत्ति पर विदेश जाकर पढ़ाई करें, न कि परिवार की आर्थिक स्थिति पर दबाव डालें। उन्होंने आगे कहा कि आशावादी हूँ कि मेरे साथी नागरिक चुनौतियों का सामना करेंगे। मुकदमों में कभी-कभी दशकों तक देरी होती है। हमने ऐसे कई मामले देखे हैं जहां किसी व्यक्ति को विचाराधीन कैदी के रूप में वर्षों जेल में बिताने के बाद निर्दोष पाया गया है। हम जिन समस्याओं का सामना कर रहे हैं उनके समाधान में हमारी सर्वश्रेष्ठ प्रतिभाएं मदद कर सकती हैं।

मुख्य न्यायाधीश गवई ने कहा कि हालांकि मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि हमारी न्याय व्यवस्था में सुधार की सख्त ज़रूरत है, फिर भी मैं इस बात को लेकर पूरी तरह आशावादी हूँ कि मेरे साथी नागरिक इन चुनौतियों का सामना करेंगे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हमें एक पोषणकारी शैक्षणिक वातावरण का निर्माण करना होगा, पारदर्शी और योग्यता-आधारित अवसर प्रदान करने होंगे, और सबसे महत्वपूर्ण बात, भारत में कानूनी अनुसंधान और प्रशिक्षण की गरिमा और उद्देश्य को पुनर्स्थापित करना होगा। भारत की कानूनी विरासत का केवल जश्न मनाना ही पर्याप्त नहीं है।

न्यायाधीश बीआर गवई ने कहा कि हमें इसके भविष्य में निवेश करना होगा, और यह भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि हम अपने शोधकर्ताओं, अपने युवा संकाय और वकीलों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। हमें न केवल संस्थानों में, बल्कि कल्पनाशीलता, मेंटरशिप कार्यक्रमों, शोध फेलोशिप, स्थानीय नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र और नैतिक कार्यस्थलों में निवेश करने की आवश्यकता है, जो हमारे सर्वश्रेष्ठ दिमागों को रुकने या वापस लौटने के लिए प्रेरित करें।

उन्होंने कहा कि यह इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि हमारा देश और हमारी न्याय व्यवस्था अनूठी चुनौतियों का सामना कर रही है। मुकदमों में देरी कभी-कभी दशकों तक चल सकती है। हमने ऐसे मामले देखे हैं जहाँ किसी व्यक्ति को विचाराधीन कैदी के रूप में वर्षों जेल में बिताने के बाद निर्दोष पाया गया है। हमारी सर्वश्रेष्ठ प्रतिभाएँ हमें उन समस्याओं का समाधान करने में मदद कर सकती हैं जिनका हम सामना कर रहे हैं।

संक्षेप

बिहार में हर परिवार को मिलेगी 100 यूनिट फ्री बिजली, विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश सरकार देगी जनता को तोहफा

पटना। बिहार में आगामी 2025 विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जनता को राहत देने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। नीतीश सरकार ने राज्य के हर परिवार को 100 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने की योजना बनाई है। ऊर्जा विभाग की इस योजना को वित्त विभाग से मंजूरी मिल चुकी है, और जल्द ही इसे राज्य कैबिनेट की बैठक में अंतिम रूप दिया जाएगा। योजना लागू होने पर लाखों उपभोक्ताओं को सीधे लाभ मिलेगा, जिससे उनके मासिक बिजली बिल में सैकड़ों रुपये तक की बचत हो सकती है। चूंकि बिहार में 2025 में विधानसभा चुनाव होने हैं, ऐसे में इस घोषणा को राजनीतिक नजरिए से भी एक अहम दांव माना जा रहा है। यह फैसला नीतीश सरकार की तरफ से सीधे मध्यमवर्गीय और निम्न आय वर्ग के वोटर्स को साधने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। विपक्षी दल इस योजना पर अपनी प्रतिक्रिया देने की तैयारी कर रहे हैं। वहीं, केंद्र सरकार की 'पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना पहले से ही सक्रिय है, जिसके तहत लोगों को घर की छत पर सोलर पैनल लगवाकर बिजली बिल से राहत दी जा रही है।

बिहार में महागठबंधन की बैठक आज, भाजपा सांसद प्रवीण खंडेलवाल बोले- 'पीएम मोदी से घबरा गए हैं ये

नई दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने बिहार विधानसभा चुनाव, वोटर लिस्ट विवाद, दिल्ली में रामलीला के आयोजन और रोजगार मेला जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर आईएएनएस के साथ खास बातचीत की। खंडेलवाल ने राष्ट्रीय जनता दल (राजद) नेता तेजस्वी यादव की ओर से बिहार में की बैठक बुलाए जाने पर तंज कसा और महागठबंधन के साथियों को चोर-चोर मौसेरे भाई बताया। उन्होंने कहा, ये चोर-चोर मौसेरे भाई हैं, जो एक बार फिर चोरी करने के इरादे से इक_ा हुए हैं। पीएम नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में एनडीए सरकार ने विकास के बड़े-बड़े काम किए हैं। इनसे घबराकर विपक्षी दल एकजुट हो रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए को पूर्ण बहुमत मिलेगा। खंडेलवाल ने विपक्ष को मेंढक करार देते हुए कहा कि लोकसभा चुनावों की तरह इस बार भी उनकी कोशिशें नाकाम होंगी। बिहार में वोटर लिस्ट संशोधन को लेकर उठे विवाद पर खंडेलवाल ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा, विपक्ष की आदत बन गई है कि हार के बाद चुनाव आयोग और ईवीएम पर आरोप लगाए। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि चुनाव आयोग ने विशेष गहन संशोधन (एसआईआर) अपने अधिकार क्षेत्र में रहकर कराया है। केवल पात्र व्यक्तियों को ही वोटर लिस्ट में शामिल करने का अधिकार आयोग को है। विपक्ष को चिंता क्यों है? क्योंकि उन्होंने बड़ी संख्या में फर्जी वोटर बनाए हैं। प्रवीण खंडेलवाल ने दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को पत्र लिखकर रामलीला आयोजन के लिए विशेष व्यवस्था की मांग की। उन्होंने कहा, जिस तरह दिल्ली सरकार ने कांवड़ यात्रा की व्यवस्था की, उसी तरह रामलीला के लिए मैदान मुफ्त में उपलब्ध कराया जाए।

पीएम मोदी ने 51,000 युवाओं को बांटे नियुक्ति पत्र; बोले- बिना पर्ची, बिना खर्ची हो रही भर्ती

नई दिल्ली, एजेंसी। देशभर के 47 शहरों में शनिवार को रोजगार मेले का आयोजन हुआ। इस दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने देशभर के युवाओं को एक बड़ी सौगात देते हुए 51,000 से ज्यादा नियुक्ति पत्र बांटे। साथ ही पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए युवाओं को संबोधित भी किया। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य पारदर्शी और ईमानदार भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाना है। पीएम मोदी ने कहा कि देश के लाखों युवाओं को ऐसे रोजगार मेलों के माध्यम से नौकरी मिली है और वे आज राष्ट्र निर्माण में योगदान दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारा मंत्र है.. 'बिना पर्ची, बिना खर्ची'।

रोजगार मेले के आयोजन का लक्ष्य

गौरतलब है कि केंद्र सरकार की तरफ से आयोजित रोजगार मेला एक विशेष अभियान है, जिसका उद्देश्य युवाओं को तेज और पारदर्शी तरीके से सरकारी नौकरियों में नियुक्त करना है। इसके तहत अब तक लाखों युवाओं को केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों में रोजगार मिल चुका है। प्रधानमंत्री मोदी के अनुसार, इस अभियान ने यह विश्वास जगाया है कि सरकारी नौकरी अब सिफारिश या रिश्वत के बिना भी मिल सकती है, केवल काबिलियत के आधार पर।

देश की विकास रफ्तार तेज करेंगे ये युवा- पीएम मोदी

युवाओं के संबोधन के दौरान पीएम मोदी ने कहा कि अलग-अलग विभागों में नियुक्त हो रहे ये युवा आने वाले समय में देश के विकास की रफ्तार को तेज करेंगे। उन्होंने कहा कि कुछ देश की रक्षा करेंगे, कुछ 'सबका साथ, सबका विकास' के सच्चे सिपाही बनेंगे। कुछ वित्तीय समावेशन मिशन को मजबूत करेंगे, तो कुछ उद्योगों के विकास में योगदान देंगे।

राष्ट्र सेवा ही सबसे बड़ी पहचान- पीएम मदी

इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि भले ही नियुक्ति पाने वाले युवाओं के विभाग अलग-अलग हैं, लेकिन उनका उद्देश्य एक ही है राष्ट्र सेवा। उन्होंने कहा कि आपके विभाग अलग हो सकते हैं, लेकिन आप सब एक ही शरीर के अंग हैं, और वह है- देश की सेवा। बता दें कि इस दौरान पीएम मोदी ने खास तौर पर इस बात पर जोर दिया कि रोजगार मेले के अभियान ने यह विश्वास जगाया है कि सरकारी नौकरी अब सिफारिश या रिश्वत के बिना भी मिल सकती है, केवल काबिलियत के आधार पर।

विकसित केरल अब भारतीय जनता पार्टी का मिशन : अमित शाह

नई दिल्ली, एजेंसी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने तिरुवनंतपुरम में भाजपा की केरल इकाई के मुख्यालय का उद्घाटन किया। केरल भाजपा अध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर भी मौजूद रहे। इस दौरान अमित शाह ने कहा कि केरल एक पवित्र भूमि है, क्योंकि यहीं श्री आदि शंकराचार्य जैसी महान आत्मा का जन्म हुआ था। आज, मैं श्री आदि शंकराचार्य की पुण्य आत्मा को नमन करता हूँ। आज केरल में भाजपा कार्यालय का उद्घाटन करते हुए, मैं उन सभी पार्टी कार्यकर्ताओं के बलिदान को याद कर रहा हूँ जिन्होंने अपनी लगन और निष्ठा से हमारी पार्टी की विचारधारा को आगे बढ़ाया है। मैं उनके बलिदान को नमन करता हूँ।

अमित शाह ने कहा कि भाजपा ने कार्यकर्ता सम्मेलन को अन्य राजनीतिक दलों के सार्वजनिक सम्मेलनों जितना ही बड़ा बना दिया है और यह केरल में भाजपा के भविष्य का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि केरल के विकास के लिए प्रधानमंत्री मोदी के तीन मुख्य दृष्टिकोण हैं- भ्रष्टाचार रहित शासन, सरकारी योजनाओं में कोई भेदभाव नहीं और राजनीतिक लाभ से परे केरल का विकास। उन्होंने कहा कि भाजपा और माकपा दोनों ही कैडर-आधारित पार्टियाँ हैं, लेकिन दोनों में एक बड़ा अंतर है। केरल में कैडर कल्याण राज्य के विकास से बड़ा है, जबकि भाजपा के लिए कैडर से ऊपर विकसित केरलम है।

शाह ने कहा कि विकसित भारत का मार्ग विकसित केरल से होकर जाता है। शक्तिशाली दक्षिणी राज्यों के विकास के बिना, एक विकसित भारत संभव नहीं है। विकसित केरल अब भारतीय जनता पार्टी का मिशन बन गया है। अमित शाह ने इस साल होने वाले स्थानीय निकाय चुनावों और अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी के अभियान की शुरुआत करने से पहले शनिवार को तिरुवनंतपुरम में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की प्रदेश समिति के नए कार्यालय मरार्जी भवन का उद्घाटन किया। शाह ने पार्टी का झंडा फहराया, भवन के सामने एक पौधा लगाया और परिसर में प्रवेश करने के लिए रिबन काटा तथा नए कार्यालय के आधिकारिक उद्घाटन के अवसर पर पारंपरिक दीप प्रज्वलित किया। शुक्रवार देर रात केरल पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री ने भाजपा की केरल इकाई के पूर्व अध्यक्ष दिवंगत के जी मरार की कांस्य प्रतिमा पर भी पुष्पांजलि अर्पित की, जिसे नए भवन के केंद्रीय कक्ष में स्थापित किया गया है।

अब नेपाल के रास्ते भारत को दहलाने की तैयारी, जैश और लश्कर के प्लान का हुआ खुलासा

नई दिल्ली, एजेंसी। पिछले दिनों पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत की सुरक्षा एजेंसियां पहले से ही सतर्क थीं, और अब नेपाल की ओर से आई चेतावनी ने खतरे की गंभीरता को और भी बढ़ा दिया है। नेपाल के एक शीर्ष अधिकारी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि पाकिस्तान समर्थित आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा नेपाल की ज़मीन का इस्तेमाल भारत में हमले करने के लिए कर सकते हैं।

काठमांडू में हुए एक अहम सम्मेलन दक्षिण एशिया में आतंकवाद : क्षेत्रीय शांति और सुरक्षा की चुनौती में नेपाल के राष्ट्रपति के सलाहकार सुनील बहादुर थापा ने कहा कि भारत-नेपाल के बीच खुली सीमा और वीज़ा-फ्री यात्रा व्यवस्था का आतंकवादी फायदा उठा सकते हैं। यह कार्यक्रम नेपाल इंस्टीट्यूट फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन एंड एंगेजमेंट द्वारा आयोजित किया गया था।

नेपाल के सांसद शिशिर खनाल ने कहा कि अब भारत और नेपाल को मिलकर बॉर्डर मैनेजमेंट को मजबूत करना होगा। उन्होंने सुझाव दिया कि हाईटेक निगरानी तकनीक का उपयोग हो, इंटेलिजेंस साझा किया जाए, और संयुक्त आतंकवाद विरोधी ऑपरेशंस शुरू किए जाएं।

नेपाल के पूर्व रक्षा मंत्री मिनेंद्र रिजाल ने पाकिस्तान की आतंकवाद को समर्थन देने की नीति की आलोचना की और कहा कि इससे भारत, नेपाल और खुद पाकिस्तान को नुकसान हो रहा है।

अजित डोभाल के 'ऑपरेशन सिंदूर' की सफलता पर दिए बयान से बौखलाया पाकिस्तान, अंतर्राष्ट्रीय नियमों की दी दुहाई

नई दिल्ली, एजेंसी। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (एनएसए) अजित डोभाल की ओर से 'ऑपरेशन सिंदूर' की सफलता पर दिए गए बयान से पाकिस्तान तिलमिला उठा है। डोभाल ने शुक्रवार को पहली बार पाकिस्तान की बखिया उधेड़ते हुए कहा कि भारत ने पाकिस्तान के भीतर मौजूद नौ आतंकी ठिकानों को बेहद सटीक तरीके से निशाना बनाया और इस दौरान एक भी चूक नहीं हुई। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन मात्र 23 मिनट में पूरा हुआ और इसका आधार पूरी तरह खुफिया जानकारी थी। अब पाकिस्तान के हुक्मरान भारतीय एनएसए के इस खुलासे पर बौखला गए हैं।

दरअसल, डोभाल ने विदेशी मीडिया को चुनौती देते हुए कहा था कि अगर भारत को नुकसान पहुंचा है, तो एक भी फोटो, एक भी सैटेलाइट इमेज दिखा दें। यहां तक कि एक शीशा भी टूटा हो तो बताएं। हम जानते थे कौन कहां है और हमने उसी जगह को निशाना बनाया। हमसे कोई चूक नहीं हुई।

डोभाल के इस बयान के बाद पाकिस्तान में खलबली मच गई। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डोभाल के बयान को 'तोड़फोड़ और झूठ से भरा हुआ' करार दिया। इसके साथ ही पाकिस्तान ने भारत पर संप्रभुता के उल्लंघन और अंतरराष्ट्रीय कानूनों की धज्जियां उड़ाने का आरोप लगाया।

पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता शफकत अली खान ने कहा, डोभाल का बयान एक जानबूझकर किया गया झूठा प्रचार है। यह जिम्मेदार कूटनीति के सभी मानकों का उल्लंघन है। भारत का इस तरह सैन्य हमले पर घमंड करना संयुक्त राष्ट्र चार्टर का गंभीर उल्लंघन है।

साथ ही यह भी आरोप लगाया गया कि भारत ने जिन लक्ष्यों को आतंकी ठिकाने बताया, वो असल में आम नागरिकों के इलाके थे और वहां नागरिकों की मौतें हुईं। शफकत अली खान ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय समुदाय को अब इसे गंभीरता से लेना होगा। अगर लगाम नहीं लगाई गई, तो हम इसके परिणाम देख चुके हैं।

बिहार में हर परिवार को मिलेगी 100 यूनिट फ्री बिजली, विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश सरकार देगी जनता को तोहफा

पटना। बिहार में आगामी 2025 विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जनता को राहत देने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। नीतीश सरकार ने राज्य के हर परिवार को 100 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने की योजना बनाई है।

ऊर्जा विभाग की इस योजना को वित्त विभाग से मंजूरी मिल चुकी है, और जल्द ही इसे राज्य कैबिनेट की बैठक में अंतिम रूप दिया जाएगा। योजना लागू होने पर लाखों उपभोक्ताओं को सीधे लाभ मिलेगा, जिससे उनके मासिक बिजली बिल में सैकड़ों रुपये तक की बचत हो सकती है। चूंकि बिहार में 2025 में विधानसभा चुनाव होने हैं, ऐसे में इस घोषणा को राजनीतिक नजरिए से भी एक अहम दांव माना जा रहा है। यह फैसला नीतीश सरकार की तरफ से सीधे मध्यमवर्गीय और निम्न आय वर्ग के वोटर्स को साधने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है।

विपक्षी दल इस योजना पर अपनी प्रतिक्रिया देने की तैयारी कर रहे हैं। वहीं, केंद्र सरकार की 'पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना' पहले से ही सक्रिय है, जिसके तहत लोगों को घर की छत पर सोलर पैनल लगवाकर बिजली बिल से राहत दी जा रही है।

शिंदे गुट के मंत्री के बैग वाले वायरल वीडियो पर घमासान, राउत ने उठाए सवाल, कहा- कपड़े थे तो दिखाओ

मुंबई, एजेंसी। शिवसेना (यूबीटी) के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद संजय राउत ने शनिवार को एक वायरल वीडियो को लेकर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पर सवाल खड़े किए। राउत ने कहा कि शिरसाट का दावा है कि बैग में सिर्फ कपड़े थे, लेकिन यदि ऐसा है तो बैग खोलकर दिखा देना चाहिए। उन्होंने कहा कि जो वीडियो में है, वो सभी ने देखा। अगर कपड़े थे तो दिखाने में क्या हर्ज था?

बता दें कि ये विवाद तब शुरू हुआ है, जब हाल ही में सोशल मीडिया पर एक वीडियो चर्चा का विषय बना हुआ है, जिसमें शिंदे गुट के मंत्री संजय शिरसाट एक कमरे में बैठे दिख रहे हैं, उनके पास ही एक बैग रखा है। दावा किया जा रहा है कि इस बैग में नोटों की गड्डियों जैसा कुछ

नजर आ रहा है।

राउत ने फडणवीस पर उठाए सवाल

इस वीडियो के सोशल मीडिया पर वायरल होने के साथ ही महाराष्ट्र की सियासत में अलग तरह की गर्माहट देखने को मिल रही है। राउत ने मुख्यमंत्री फडणवीस की चुप्पी पर सवाल उठाते हुए कहा कि शिवसेना (शिंदे गुट) ने सरकार को मजाक बना दिया है और मुख्यमंत्री इस पर चुप हैं। क्या ये सरकार को चलाने का तरीका है? इसके साथ ही राउत ने शिवसेना विधायक संजय गायकवाड़ पर भी हमला बोला। हाल ही में गायकवाड़ पर मुंबई के विधायक हॉस्टल की कैंटीन के कर्मचारी के साथ मारपीट का आरोप लगा था। पुलिस ने उनके खिलाफ गैर-संज्ञेय अपराध दर्ज किया है। राउत ने कहा कि यह साधारण मामला नहीं, हत्या के प्रयास जैसा है। सरकार ऐसे अपराधियों को क्यों बचा रही है?

महाराष्ट्र विशेष सार्वजनिक सुरक्षा विधेयक 2024 पर भी साधा निशाना

अंत में राउत ने राज्य विधान परिषद में पास हुए महाराष्ट्र विशेष सार्वजनिक सुरक्षा विधेयक 2024 को लोकतंत्र विरोधी करार दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि यह कानून आदिवासी और सामाजिक कार्यकर्ताओं की आवाज दबाने के लिए लाया गया है। उन्होंने कहा कि भाजपा को उन लोगों से डर लगता है जो आदिवासियों के लिए लड़ते हैं।

'शिंदे गुट दिल्ली के प्यादे'

इसके अलावा राउत ने एकनाथ शिंदे गुट पर जोरदार हमला किया। उन्होंने कहा कि शिंदे गुट के साथ हमारी दुश्मनी अब ऐसी हो गई है कि आमने-सामने बैठना भी मुश्किल है। उन्होंने शिंदे गुट को दिल्ली का प्यादा और महाराष्ट्र का दुश्मन कहा।

एयर इंडिया विमान हादसे की प्रारंभिक रिपोर्ट में खुलासा, उड़ान के बाद दोनों इंजन हुए थे बंद

नई दिल्ली, एजेंसी। एयर इंडिया के बोइंग 787-8 विमान के इंजन के फ्यूल कंट्रोल स्विच टेकऑफ के तीन सेकंड बाद 'रन' से 'कटऑफ' की स्थिति में चले गए, जिसके कारण विमान उड़ान भरने के 34 सेकंड बाद ही दुर्घटनाग्रस्त हो गया। शनिवार को विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो (एएआईबी) की शुरुआती जांच रिपोर्ट में यह जानकारी सामने आई।

एयर इंडिया फ्लाइट 171 के इंजनों को ईंधन आपूर्ति करने वाले दोनों ईंधन नियंत्रण स्विच एक के बाद एक 'रन' से 'कटऑफ' पोजिशन में चले गए, जिससे दोनों इंजन बंद हो गए। जांच रिपोर्ट के अनुसार, कॉकपिट वॉयस रिकॉर्डर में एक पायलट को दूसरे से पूछते हुए सुना गया कि उसने ईंधन बंद क्यों किया, जिसके जवाब में दूसरा पायलट कहता है कि उसने ऐसा नहीं किया। रिपोर्ट के अनुसार, इंजन 1 और 2 के ईंधन स्विच कुछ ही सेकंड में 'रन' स्थिति में आ गए। दोनों इंजनों के ईजीटी बढ़ गए, जो बताता है कि पुनः रिलाइट प्रक्रिया शुरू हो गई। कॉकपिट वॉयस रिकॉर्डिंग से पता चलता है कि पायलटों में भ्रम की स्थिति थी। एक पायलट ने पूछा, आपने कट क्यों किया? दूसरे ने जवाब दिया, मैंने ऐसा नहीं किया, जिससे संभवतः गलतफहमी का संकेत मिलता है। इस उड़ान में सह-पायलट क्लाइव कुंदर विमान उड़ा रहे थे, जबकि मुख्य पायलट सुमीत सभरवाल उड़ान की निगरानी कर रहे थे। सभरवाल के पास बोइंग 787 पर करीब 8,600 घंटे का अनुभव था, जबकि कुंदर के पास 1,100 घंटे से अधिक का अनुभव था। रिपोर्ट के अनुसार, दोनों पायलटों को उड़ान से पहले पर्याप्त आराम मिला था।

15 पेज की रिपोर्ट के अनुसार, उड़ान शुरू होने से लेकर दुर्घटना तक लगभग 30 सेकंड तक चली। रिपोर्ट में कहा गया है कि फिलहाल जांच में ऐसा कुछ नहीं मिला है जिसके आधार पर बोइंग 787-8 विमान और जीई जेनएक्स-1बी इंजन बनाने वाली कंपनी के लिए कोई चेतावनी जारी करनी पड़े। प्रारंभिक रिपोर्ट में बताया गया है कि अमेरिकी फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन (एफएए) ने 2018 में एक विशेष सूचना बुलेटिन (एसएआईबी) जारी किया था, जिसमें ईंधन नियंत्रण स्विच की लॉकिंग सुविधा के अलग होने की संभावना के बारे में चेतावनी दी गई थी।

प्रयागराज जंक्शन पर गुजरात के रोहित ने की थी रेलकर्मी अमित की नृशंस हत्या

आर्यावर्त संवाददाता

प्रयागराज। नौ जुलाई 2025 की रात लगभग साढ़े नौ बजे प्रयागराज जंक्शन के प्लेटफार्म नंबर सात-आठ पर रेलकर्मी अमित कुमार पटेल की लोहे के एंगल से बेरहमी से पीट-पीटकर हत्या कर दी गई। इस हत्याकांड ने न केवल रेलवे प्रशासन को हिलाकर रख दिया, बल्कि स्थानीय लोगों और पुलिस के लिए भी कई अनुत्तरित सवाल छोड़ दिए।

हत्या का आरोपित गुजरात के बनासकांठा जिले के जोहड़ा गांव का रहने वाला रोहित मकवाना था। जिसकी इसी घटना में ट्रेन की चपेट में आने से मौत हुई थी। शनिवार की सुबह रोहित के पिता और भाइयों ने पोस्टमार्टम हाउस में शव की शिनाख्त की, जिसके बाद इस मामले में कई नए तथ्य सामने आए। हालांकि, हत्या के पीछे का कारण अभी भी एक रहस्य बना हुआ है।

बुधवार रात प्रयागराज जंक्शन पर रेलकर्मी अमित कुमार पटेल ड्यूटी पर तैनात थे। उन पर अचानक लोहे के एंगल से हमला किया गया। हमलावर ने अमित पर ताबड़तोड़ प्रहार किए, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। हमले की क्रूरता ऐसी थी कि आसपास मौजूद लोग स्तब्ध रह गए। हमलावर, जिसकी बाद में पहचान रोहित मकवाना के रूप में हुई, हमले के तुरंत बाद रेलवे ट्रैक पर भागा, एक आरपीएफ कांस्टेबल पर भी उसने हमला किया जिसमें वह गंभीर रूप से घायल हो गए। जबकि वेंडर, यात्रियों को भी उसने मारने के लिए दौड़ाया था। कुछ साहसी यात्रियों ने उसे पकड़ा लेकिन वह ट्रेन की ओर भागा, ट्रेन के पहिए के नीचे आकर मर गया। घटनास्थल से पुलिस को एक टूटा हुआ मोबाइल फोन मिला, जो इस मामले की जांच में महत्वपूर्ण साबित हुआ। मोबाइल की कॉल डिटेल रिकॉर्ड (सीडीआर) और उसमें मौजूद जानकारी ने पुलिस को रोहित की पहचान करने में मदद की। रोहित के हाथ पर बना एक टैटू, जिसमें देवी चामुंडा और आईएमआर (जिसका मतलब "आई एम रोहित" बताया गया) लिखा था। इससे इसने शिनाख्त में अहम भूमिका निभाई। जीआरपी (गवर्नमेंट रेलवे पुलिस) ने तुरंत रोहित के परिजनों से संपर्क किया और टैटू की तस्वीरें भेजीं, जिसके आधार पर परिजनों ने शव की पुष्टि की।

रोहित की मानसिक स्थिति और संभावित कारण

रोहित के परिजनों ने पुलिस को बताया कि पिछले तीन महीनों से उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी। वह छोटी-छोटी बातों पर गुस्सा हो जाता था और कई बार बिना बताए घर से चला जाता था। हालांकि, गांव में उसका किसी से कोई विवाद नहीं था, और वह एक सीधा-सादा इंसान था। परिजनों के इस बयान ने जांच को एक नई दिशा दी है। क्या रोहित ने मानसिक अस्थिरता के कारण अमित पर हमला किया? या फिर अमित और रोहित के बीच कोई ऐसी घटना हुई, जिसके बारे में परिजनों को जानकारी नहीं है?

रोहित मकवाना: कौन था यह शख्स?

रोहित मकवाना गुजरात के बनासकांठा जिले के जोहड़ा गांव का रहने वाला था। उसके पिता रता जी सुंदा जी मकवाना ने बताया कि रोहित उनके चार बेटों में दूसरा था। उसका बड़ा भाई मेरू और दो छोटे भाई लक्ष्मण और शैलेश हैं। रोहित की शादी छह साल पहले राजस्थान के मारवाड़ में हुई थी, और उसकी पत्नी मीरा के साथ उसके तीन बच्चे हैं। एक पांच साल की बेटी, एक तीन साल का बेटा और एक छह महीने की दूसरी बेटी। रोहित अपने परिवार के साथ गांव में खेती और मजदूरी करके जीवनयापन करता था।

स्वजनों के अनुसार, रोहित पिछले तीन महीनों से मानसिक रूप से अस्थिर था। वह अचानक गुस्सा हो जाता था और बिना बताए घर से कहीं चला जाता था। हालांकि, कुछ दिनों बाद वह वापस लौट आता था। इस बार भी जब वह 6 जुलाई को घर से निकला, तो उनको लगा कि वह जल्द लौट आएगा। रोहित ने 7 जुलाई को अपने भाई शैलेश को फोन कर बताया कि वह अपनी ससुराल मारवाड़ जा रहा है। लेकिन इसके बाद उसका कोई संपर्क नहीं हुआ। 10 जुलाई को जीआरपी ने रोहित के पिता को फोन कर सूचना दी कि प्रयागराज जंक्शन पर एक शव मिला है, जिसके टैटू और अन्य विशेषताओं से उसकी पहचान रोहित के रूप में हुई। रोहित के पिता और भाई शनिवार की सुबह प्रयागराज के पोस्टमॉर्टम हाउस पहुंचे। रोहित के सिर और टैटू को देखते ही वे बिलखने लगे। उन्होंने पुष्टि की कि यह शव रोहित का ही है। पोस्टमॉर्टम के बाद शव को एंबुलेंस से उनके पैतृक गांव जोहड़ा ले जाया गया। परिजनों ने अभी रोहित की पत्नी मीरा को उसकी मृत्यु की खबर नहीं दी है, क्योंकि वे नहीं चाहते कि उसे अचानक इतना बड़ा सदमा लगे।

जांच में प्रगति, पर रहस्य बरकरार

जीआरपी ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए हमलावर की पहचान तो कर ली, लेकिन हत्या के पीछे का मकसद अभी तक स्पष्ट नहीं हो सका है। पुलिस ने घटनास्थल से मिले टूटे मोबाइल फोन और उसमें मौजूद जानकारी के आधार पर रोहित के परिजनों से संपर्क किया। मोबाइल की सीडीआर से पता चला कि फोन रोहित का था, और उसके परिजनों ने टैटू की तस्वीरों के आधार पर उसकी शिनाख्त की। लेकिन सवाल यह है कि रोहित ने अमित की हत्या क्यों की? क्या दोनों के बीच कोई पुरानी रंजिश थी? या फिर यह हमला किसी मानसिक अस्थिरता का परिणाम था? पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की भी जांच की, जिसमें रोहित को लोहे का एंगल पीठ पीछे छिपाकर रेलवे ट्रैक पार करते और अमित पर हमला करते देखा गया। फुटेज में यह स्पष्ट है कि रोहित ने जानबूझकर अमित को ही निशाना बनाया, जबकि आसपास कई अन्य लोग भी मौजूद थे। यह व्यवहार सामान्य नहीं लगता और कई सवाल खड़े करता है। रोहित प्रयागराज कैसे और क्यों पहुंचा, यह भी एक रहस्य है। परिजनों का कहना है कि रोहित का प्रयागराज से कोई संबंध नहीं था, और वह पहले कभी वहां नहीं गया था।

सवाल गहरे पर जवाब नहीं

प्रयागराज जंक्शन पर अमित हत्याकांड ने न केवल एक परिवार को सदमे में डाल दिया, बल्कि समाज के सामने कई गंभीर सवाल भी खड़े किए हैं। रोहित मकवाना द्वारा अमित कुमार पटेल की हत्या और उसके बाद रोहित की स्वयं की मृत्यु ने इस मामले को और जटिल बना दिया है। जीआरपी ने हमलावर की पहचान तो कर ली, लेकिन हत्या का मकसद अभी तक एक रहस्य बना हुआ है। क्या यह मानसिक अस्थिरता का परिणाम था, या इसके पीछे कोई व्यक्तिगत रंजिश थी? इस सवाल का जवाब अभी तक किसी के पास नहीं है। पुलिस की जांच अभी भी जारी है, और उम्मीद है कि जल्द ही इस मामले में कुछ और तथ्य सामने आएंगे। तब तक, यह घटना न केवल एक दहशत और डर के रूप में याद की जाएगी, बल्कि यह समाज को मानसिक स्वास्थ्य, सुरक्षा, और संवेदनशीलता जैसे मुद्दों पर विचार करने के लिए भी मजबूर करेगी।

जीआरपी ने मामले में साधी चुप्पी

जीआरपी इस मामले में अभी तक चुप्पी साधे हुए है। पुलिस का कहना है कि वे सभी पहलुओं की जांच कर रहे हैं, लेकिन हत्या के पीछे का मकसद स्पष्ट करने के लिए अभी और सबूतों की जरूरत है। अमित के परिजनों से भी पुलिस ने पूछताछ की, लेकिन उन्हें भी रोहित के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। अमित एक मेहनती रेलकर्मी थे, और उनका किसी से कोई विवाद होने की बात सामने नहीं आई है।

NGT के आदेश के बाद नोएडा में यहां खूब गरजा गरजा बुलडोजर, 30 हजार वर्ग मीटर जमीन कब्जा मुक्त

आर्यावर्त क्रांति ब्यूरो

ग्रेटर नोएडा। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने हैबतपुर के डूब क्षेत्र में अतिक्रमण के खिलाफ शुक्रवार को बुलडोजर चलाया। प्राधिकरण ने करीब 30 हजार वर्ग मीटर डूब क्षेत्र को अतिक्रमण से मुक्त करा लिया है। हरनंदी नदी के किनारे कालोनाइजर से जमीन लेकर लोगों ने घर बना लिए थे, जिसे एनजीटी के आदेश पर ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने तोड़ दिया।

दरअसल, डूब क्षेत्र में अतिक्रमण के खिलाफ दायर एक याचिका पर सुनवाई करते हुए एनजीटी ने सिंचाई विभाग से कार्रवाई कर रिपोर्ट मांगी थी। प्राधिकरण के अधिसूचित क्षेत्र में होने के नाते ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण व सिंचाई विभाग ने पुलिस के सहयोग से यह कार्रवाई की।

ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के महाप्रबंधक एके सिंह ने बताया कि ग्राम हैबतपुर के खसरा संख्या 209, 210, 211, 212, 213 और 217 की जमीन हरनंदी नदी के डूब क्षेत्र में आता है। डूब क्षेत्र होने के बावजूद कालोनाइजर चोरी-छिपे प्लाटिंग कर रहे हैं। शिवम एन्क्लेव के नाम से अवैध कालोनी बसा रहे थे।

दूरदराज से रोजगार की तलाश में आने वाले लोग घर की चाहत में इन कालोनाइजर से जमीन खरीदकर निर्माण कर लिए थे। इन लोगों को प्राधिकरण की तरफ से नोटिस भी जारी अतिक्रमण हटाने को कहा गया था, लेकिन कोई असर नहीं पड़ा।

एनजीटी के आदेश पर प्राधिकरण के परियोजना विभाग के वर्क सर्किल एक के प्रभारी प्रभात शंकर के नेतृत्व में सिंचाई विभाग व पुलिस के सहयोग से अवैध निर्माण को ढहा दिया गया। इस कार्रवाई में 10 से अधिक निर्मित घर और 24 के करीब चारदीवारी को तोड़ दिया गया।

सुबह करीब साढ़े पांच बजे से कार्रवाई शुरू हुई और तीन घंटे तक चली। इस कार्रवाई में पांच जेसीबी और तीन डंपरों का इस्तेमाल किया गया। अतिक्रमण हटाने के दौरान महाप्रबंधक एके सिंह और प्रभारी वरिष्ठ प्रबंधक प्रभात शंकर के अलावा वरिष्ठ प्रबंधक राजेश कुमार निम, वरिष्ठ प्रबंधक विनोद शर्मा, पुलिस अफसर दीक्षा सहित प्राधिकरण की टीम और बड़ी संख्या में पुलिस बल मौजूद रहा।

ग्रेनो प्राधिकरण के एसीईओ सुमित यादव ने अतिक्रमण करने वाले को चेतावनी दी है कि ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की अधिसूचित क्षेत्र में अनुमति के बिना या फिर बिना नक्शा पास कराए बिना अवैध निर्माण करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी, फिर वह क्षेत्र चाहे डूब क्षेत्र ही क्यों न हो।

एसीईओ ने लोगों से भी अपील की है कि ग्रेटर नोएडा में कहीं भी जमीन खरीदने से पहले प्राधिकरण से संपर्क कर पूरी जानकारी जरूर प्राप्त कर लें। अवैध कालोनी में अपनी गाढ़ी कमाई न फंसाएं।

पेशी पर आये व्यक्ति को जान से मारने की धमकी

सुलतानपुर। एक व्यक्ति को कोर्ट में पेशी के बाद चाय की दुकान पर जान से मारने की धमकी दी गई। इस मामले में एसपी से मिलकर पीड़ित ने शिकायत कर न्याय की गुहार लगाई है। कोतवाली नगर के शाहगंज निवासी जयप्रताप सिंह मारुति इन्फ्रा प्राइवेट लिमिटेड लखनऊ में कार्यरत हैं। कोर्ट नंबर 4 में चल रहे केस एसटी नंबर 301/2013 की पेशी के लिए 5 जुलाई को आए थे। पेशी के बाद वे अपने साथी जय प्रकाश यादव और मुंशी सभाजीत मिश्रा के साथ कोर्ट के गेट नंबर एक के सामने स्थित चाय की दुकान पर बैठे थे। इसी दौरान विपक्षी जैसराज यादव का भतीजा कोतवाली देहात अंतर्गत सराय अचल निवासी नवरत्न यादव उर्फ रिशू वहां आया। उसने जयप्रकाश यादव और जयप्रताप सिंह को गालियां दीं और जान से मारने की धमकी दी। दुकान पर मौजूद लोगों ने बीच-बचाव किया। नवरत्न यादव ने कहा, 'जब चाहूंगा तब जान से मार दूंगा।' जय प्रकाश यादव ने इस पूरी घटना का वीडियो अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया। चाय की दुकान से कुछ दूरी पर नवरत्न के चचेरे भाई आकाश यादव, सगे भाई हिमांशु यादव और 2-3 अन्य लोग खड़े थे। जयप्रताप सिंह और जय प्रकाश यादव बचते-बचाते अपने घर चले गए। मोहर्रम के कारण पुलिस की व्यस्तता के चलते शिकायत दर्ज करने में देरी हुई। जयप्रताप सिंह ने पुलिस अधीक्षक सुलतानपुर से अपनी जान-माल की सुरक्षा और उचित कार्यवाही की मांग की है।

शिक्षकों की हुंकार मर्जर नीति नहीं चलेगी, शिक्षा के अधिकार पर कोई समझौता नहीं

आर्यावर्त संवाददाता

सुलतानपुर। विद्यालयों मर्जर/पेयरिंग के विरोध में प्राथमिक शिक्षकों का आक्रोश एक संगठित आंदोलन के रूप में सामने आया, जब उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ शाखा सुल्तानपुर के बैनर तले जिला अध्यक्ष दिनेश उपाध्याय के नेतृत्व में मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन विधानसभा लंभुआ के विधायक सीताराम वर्मा को सौंपा गया। यह आयोजन लंभुआ ब्लॉक सभागार में संपन्न हुआ, जहां शिक्षक समुदाय ने एकजुटता और संकल्प का परिचय दिया। वहीं विधायक सीताराम वर्मा ने शिक्षकों की बातों को गंभीरता से सुनते हुए आश्वासन दिया,₹शिक्षकों की चिंता पूरी तरह से वाजिब है। मर्जर नीति पर आपकी बात और ज्ञापन को हम सरकार तक पहुंचाने में पूरी मदद करेंगे और छात्रों और शिक्षकों के हित के लिए हम मजबूती से आपके साथ खड़े मिलेंगे। हमारी प्राथमिकता बच्चों की शिक्षा और शिक्षक का सम्मान है।जिला अध्यक्ष दिनेश उपाध्याय ने कहा कि जब तक सरकार इस जनविरोधी मर्जर नीति का शासनादेश वापस नहीं लेती, संगठन का लोकतांत्रिक संघर्ष जारी रहेगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि शिक्षक सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि ग्रामीण शिक्षा की रक्षा के लिए यह आवाज उठा रहे हैं।जिला मंत्री राम आशीष मौर्य ने मर्जर नीति की सामाजिक विफलता की ओर इशारा करते हुए कहा, ₹यह व्यवस्था विशेषकर बालिकाओं की शिक्षा के लिए घातक बन रही है। ग्रामीण अभिभावक बेटियों को दूरस्थ विद्यालयों में भेजने से कतराते हैं, जिससे उनकी पढ़ाई बाधित हो रही है लंभुआ ब्लॉक अध्यक्ष रणवीर सिंह ने विद्यालय मर्जर को एक मर्ज बताया और कहा कि इसे बंद किया जाना चाहिए इस अवसर पर जिला उपाध्यक्ष एवं ब्लॉक अध्यक्ष प्रतापपुर कमैचा श्री संजय सिंह, जिला कोषाध्यक्ष श्री विनय प्रजापति, मंत्री लंभुआ द्वारिका प्रसाद यादव, ब्लॉक मंत्री भदैया विपिन यादव, जिला कमेटी के कई अन्य पदाधिकारीगण एवं सैकड़ों शिक्षकगण मौजूद रहे। यह कार्यक्रम केवल एक ज्ञापन नहीं, बल्कि ग्रामीण शिक्षा की रक्षा के लिए एक प्रेरक चेतावनी बनकर उभरा।

अरब मे दो ट्रको की टक्कर मे जिले के युवक की जलकर मौत

सुलतानपुर। रोजी-रोटी के लिए अपना वतन छोड़कर सऊदी के रियाद शहर गया देहात कोतवाली क्षेत्र के मलिकपुर गांव का एक युवक घटना का शिकार हो गया है। दो ट्रकों की भिड़ंत में एक ट्रक आग का गोला बन गई, जिसमें जिले का युवक गुलरेज अहमद जिन्दा जलकर राख हो गया। उसका पार्थिव शरीर वतन लाने के लायक नहीं है। इसकी खबर गांव में पहुंची तो मातम छा गया। गांव वाले भी घटना से स्तब्ध रह गए हैं, पारिवारिक जनों को किसी तरह शोक संवेदना व्यक्त कर संभालने में लगे हुए हैं। देहात कोतवाली क्षेत्र के मलिकपुर गांव निवासी कय्यूम अहमद के पांच बेटे हैं। उनका माझिल बेटा गुलरेज अहमद (26) ट्रक चालक था। मार्च 2024 में वह रोजी-रोटी के सिलसिले में सऊदी अरब गया। रियाद शहर की एक कंपनी में वह बतौर ट्रक ड्राइवर कार्यरत था। बताया जाता है कि शुक्रवार को वह ट्रक लेकर कहीं जा रहा था, सुबह करीब 10:30 बजे अलक़ासिम रोड पर विपरीत दिशा से आ रहे एक ट्रक ने गुलरेज की ट्रक में जोरदार टक्कर मार दी।

सनातन की आस्था... 151 किलो की कांवड़ लेकर चले मुस्लिम दोस्त, बोले– 'सनातनी पहले मुसलमान बाद में'

आर्यावर्त संवाददाता

कासगंज। सनातन की बात ही कुछ ऐसी है, जो आगरा के दो मुस्लिम दोस्त को रोक नहीं पाई। वे अपने जत्थे के साथ गंगा घाट पर पहुंचे और भागीरथ बनकर 151 किलो गंगा जल की कांवड़ लेकर गंतव्य को निकल पड़े। दोनों कहते हैं कि माता और पिता की इच्छा थी कि कांवड़ लेकर आएं और भगवान शिव का अभिषेक करें। शिव बहुत दयालु हैं, हमने सुन रखा है। हम सनातनी पहले मुस्लिम बाद में हैं। शुक्रवार को कांवड़ लेकर जसराना पहुंच गए।

आगरा जिले के थाना बाह क्षेत्र के गांव कृषा के रहने वाले 25 वर्षीय साजिद खान और उनके दोस्त 22 वर्षीय सनी खान 151 किलो की कांवड़ लेकर बटेश्वर जा रहे हैं। वे वहां 14 जुलाई को भगवान शिव का जलाभिषेक करेंगे। दोनों दोस्त कांवड़ यात्रा पर पहली बार आए हैं, लेकिन बहुत उत्साहित हैं। कह रहे हैं कि अपने गांव के तमाम लोगों को कई वर्षों से कांवड़ ले जाते हुए देख रहे थे।

दोनों भाई बोले माता-पिता की इच्छा थी कि हम कांवड़ लाएं

भगवान शिव की महिमा के बारे में सुन रखा है। इस बार अपने माता-पिता के समक्ष इच्छा प्रकट की कि हम भी कांवड़ लेकर आएंगे, तो वे तत्काल तैयार हो गए और इसके बाद अपने 10 सदस्यीय जत्थे के साथ सोरों के लहरा घाट पर आ गए, जहां से कांवड़ यात्रा शुरू कर दी। बोले कि थोड़ा ब्रेक लेकर चलना पड़ता है क्योंकि 151 किलो का वजन बहुत होता है, लेकिन गंतव्य तक पहुंचेंगे और भोले भंडारी का गंगाजल से अभिषेक करेंगे। यह भी बोले कि पुरोहितजी ने पूरे विधि-विधान, पूजा-अर्चना के साथ हमें गंगा घाट से विदा किया है। जमीन पर कांवड़ नहीं रखेंगे।

कांवड़ ले जाकर मिलेगा सुकून, माता-पिता की करेंगे सेवा

पूछा कि थकान हो रही है तो बोले कि थकान कैसी, जो कांवड़ लेकर जाता है उसमें अपने आप ताकत आ जाती है। साफ पूछा गया कि आप मुस्लिम हैं और कांवड़ लेकर जा रहे हैं, तो बीच में ही साजिद बोले, पहले तो हम सनातनी हैं, मुस्लिम बाद में। सवाल आस्था का है तो भगवान शिव भी हमारे आराध्य हैं। इन कांवड़ यात्रियों का जोश, जज्बा और जुनून देखते ही बनता है।

गोरखपुर के इस फुटपाथ को साढ़े तीन मीटर किया जाएगा चौड़ा, हो सकेगी गाड़ियों की पार्किंग

आर्यावर्त क्रांति ब्यूरो

गोरखपुर। सीएम ग्रिड के तहत बनने वाली गोलघर की सड़क अब पिंपरी चिंचवड़ नगर निगम की तर्ज पर बनाई जाएगी। इस सड़क के किनारे न सिर्फ तीन से साढ़े तीन मीटर चौड़ा फुटपाथ बनाया जाएगा बल्कि इस फुटपाथ पर पार्किंग की भी व्यवस्था होगी। हरेक 100 मीटर की दूरी पर करीब 30 मीटर की लंबाई में पार्किंग का प्रविधान किया जाएगा। साथ ही फुटपाथ दृष्टिबाधित विकलांगों के सुविधाजनक आवागमन अनुरूप बनाया जाएगा।

नगर निगम के इंजीनियरों की टीम महाराष्ट्र के पुणे स्थित पिंपड़ी चिंचवड़ नगर निगम में आयोजित कार्यशाला में शामिल होने और स्थानीय भ्रमण के बाद सीएम ग्रिड की इस सड़क की डिजाइन में बदलाव का निर्णय लिया है।

यह योजना मुख्यमंत्री ग्रीन रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम (अर्बन) के तहत बनाई जा रही है। इसके तहत शास्त्री चौक से आंबेडकर चौक होते हुए छात्रसंघ चौराहा तक, आंबेडकर चौक से हरिओम नगर तिराहा होते हुए मुख्य डाकघर तिराहा तक और हरिओम नगर से कचहरी चौराहा होते हुए टाउनहाल तक की सड़क बनाई जाएगी।

सीएम ग्रीन रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट योजना के तहत कुल तीन सड़कों का निर्माण प्रस्तावित है। इनमें कुल पांच सड़कें शामिल हैं। करीब 53.68 करोड़ की लागत से इन सड़कों का निर्माण होना है। पहली स्मार्ट सड़क 2.378 किलोमीटर लंबी और 15 मीटर चौड़ी होगी।

यह शास्त्री चौक से आंबेडकर चौक होते हुए छात्रसंघ चौराहा तक, आंबेडकर चौक से हरिओम नगर तिराहा होते हुए एस्प्रा तिराहा तक और हरिओम नगर से कचहरी चौराहा होते हुए टाउनहाल तक बनाई जाएगी।

इस सड़क के निर्माण पर करीब 27.02 करोड़ रुपये की लागत आएगी। दूसरी सड़क टाउनहाल स्थित शिवाय होटल से अग्रसेन तिराहा, विजय चौराहा होते हुए गणेश चौक तक बनेगी। इसकी लंबाई 1.250 किमी और चौड़ाई 15 मीटर होगी। इस सड़क के निर्माण पर करीब 14.84 करोड़ रुपये की लागत आएगी। तीसरी सड़क कचहरी चौराहे से काली मंदिर तक बनेगी। इस सड़क की लंबाई करीब 0.842 किलोमीटर और चौड़ाई 28 मीटर होगी। इस सड़क के निर्माण पर करीब 11.82 करोड़ रुपये आएगी।

सड़क और फुटपाथ यह होंगी ये सुविधाएं

सबसे बड़ा बदलाव फुटपाथ को लेकर किया जा रहा है। फुटपाथ की चौड़ाई बढ़ाई जाएगी। इस पर बैठने की भी व्यवस्था होगी। कुर्सी और टेबल इस तरह से डिजाइन किए जाएंगे, जहां लोग शतरंज और लूडो आदि खेल सकेंगे। वहीं फुटपाथ पर दृष्टिबाधित दिव्यांगों की सुविधा के लिए टैक्टाइल टाइल्स लगाई जाएगी।

इस टाइल्स को अपने स्टीक से स्पर्श कर दृष्टिबाधित विकलांग आसानी से चल सकेंगे। मोड़ पर टाइल्स के उभारों में बदलाव होगा, जिससे उन्हें मुड़ने की जानकारी मिल जाएगी। इसके नीचे ही नाली, बिजली के तारों के लिए डक्ट और पीने के पानी व गैस की पाइपलाइन बिछाई जाएगी।

इसका सबसे बड़ा लाभ यह होगा कि नाली, बिजली या पीने के पानी संबंधी कोई खराबी आने पर सड़क नहीं खोदनी पड़ेगी, जिससे यातायात प्रभावित नहीं होगा। वहीं, ट्रांसफार्मर को जमीन से ऊपर खंभों के सहारे ऊंचा कर लगाया जाएगा। नालियों के ढक्कन भी ऐसे होंगे जिन्हें चाबी के सहारे ही खोला जा सकेगा।

गोलघर सीएम ग्रिड की सड़क की डिजाइन में बदलाव किया जा रहा है। स्मार्ट सिटी पिंपरी चिंचवड़ की तर्ज पर यहां की सड़क बनाई जाएगी। फुटपाथ पर ही गाड़ियों की पार्किंग की भी व्यवस्था की जाएगी। आर्किटेक्ट से इस बदलाव के साथ डिजाइन तैयार कराया जा रहा है।

अमित कुमार शर्मा, मुख्य अभियंता नगर निगम

भड़ेवरा कांड में गिरफ्तार लोगों से जेल में मिले कांग्रेस नेता

आर्यावर्त संवाददाता

प्रयागराज। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय, कांग्रेस सांसद तनुज पुनिया और कांग्रेस सांसद उज्जवल रमण सिंह ने आज नैनी जेल में करछना में विगत दिनों हूए बवाल में नैनी जेल में बंद दलित और आदिवासी समुदाय के लोगों से मुलाकात की। मुलाकात के बाद तीनों नेताओं ने संयुक्त रूप से कहा कि कांग्रेस पार्टी जेल में बंद सभी लोगों को हर संभव मदद मुहैया कराएगी और उनकी कानूनी लड़ाई में भी पूरा सहयोग करेगी। अजय राय ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि करछना में जो कुछ हुआ वह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। जिस तरह से दलित और आदिवासी समुदाय के लोगों को निशाना बनाया गया है, वह अस्वीकार्य है। हम उन्हें अकेला नहीं छोड़ेंगे और सुनिश्चित करेंगे कि उन्हें न्याय मिले। सांसद तनुज पुनिया ने इस बात पर जोर दिया कि कांग्रेस पार्टी इस मामले को गंभीरता से ले रही है। उज्जवल रमण सिंह ने भी अपनी बात रखते हुए कहा, 'कांग्रेस हमेशा से वंचितों और पीड़ितों के साथ खड़ी रही है। हम यह सुनिश्चित करेंगे कि जेल में बंद इन दलित और आदिवासी भाइयों को किसी भी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े और उन्हें जल्द से जल्द न्याय मिल सके। कांग्रेस नेताओं ने यह भी कहा कि वे इस मामले में निष्पक्ष जांच की मांग करेंगे और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए सरकार पर दबाव बनाएंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रशासन ने करछना घटना को लेकर एकतरफा कार्रवाई की है, जिससे दलित और आदिवासी समुदाय में रोष है। उक्त अवसर पर सर्वश्री पूर्व शहर कांग्रेस अध्यक्ष प्रदीप मिश्रा अंशुमन, मोहम्मद असलम, इरशाद उल्ला, दिवाकर भारतीय, शादाब अहमद, प्रवीण सिंह भोले, रियाज अहमद, मोहम्मद फरहान, लल्लन पटेल ,रमेश यादव, विष्णु पांडे आदि कांग्रेस जन उपस्थित रहे।

उत्तर प्रदेश में विश्व युवा कौशल दिवस-2025 पर भव्य कौशल ओलिंपिक का आयोजन

लखनऊ। विश्व युवा कौशल दिवस-2025 के अवसर पर उत्तर प्रदेश सरकार राजधानी लखनऊ में 15 और 16 जुलाई को कौशल ओलिंपिक का भव्य आयोजन करने जा रही है। यह कार्यक्रम उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन के तहत आयोजित होगा, जिसका उद्देश्य युवाओं के नवाचारों को एक मंच प्रदान करना है, विशेषकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे आधुनिक तकनीकी क्षेत्रों में किए गए टेक-बेस्ड कौशल नवाचारों को प्रस्तुत करना।मिशन निदेशक पुलकित खरे ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मार्गदर्शन में यह आयोजन किया जा रहा है। राज्य के सभी जनपदों में संचालित प्रशिक्षण केंद्रों से चयनित प्रतिभागी इस ओलिंपिक में हिस्सा लेकर अपने प्रोजेक्ट्स, मॉडल्स, ऐप्स और टेक्नोलॉजी आधारित समाधानों का प्रदर्शन करेंगे।

गुरु तेगबहादुर सन्देश यात्रा को मुख्यमंत्री योगी ने दिखाई हरी झंडी, शहादत की विरासत को बताया भारत की नींव

आर्यावर्त क्रांति ब्यूरो

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को अपने सरकारी आवास से श्री गुरु तेगबहादुर जी महाराज के 350वें शहीदी वर्ष को समर्पित श्री गुरु तेगबहादुर सन्देश यात्रा को पुष्पवर्षा कर रवाना किया। यह यात्रा लखनऊ के नाका हिण्डोला स्थित श्री गुरु सिंह सभा से प्रारंभ होकर दिल्ली के चांदनी चौक स्थित गुरुद्वारा श्री शीशगंज साहिब तक जाएगी।इससे पहले मुख्यमंत्री ने पावन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के स्वरूप को अपने शीश पर धारण कर स्वागत किया और उन्हें आसन पर विराजमान किया। उन्होंने श्रद्धाभाव से मत्था टेका और शबद-कीर्तन कार्यक्रम में सहभागिता की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री को गुरु तेगबहादुर जी का चित्र, अंगवस्त्र और स्मृति चिह्न भेंट किया गया।मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यह सन्देश यात्रा शहीदों की स्मृति को जीवंत रखने और वर्तमान व भावी पीढ़ियों को प्रेरणा देने वाला कदम है। उन्होंने कहा कि लखनऊ से दिल्ली तक निकाली जा रही यह यात्रा बलिदान, त्याग और आत्मबल की प्रतीक है, जो भारत के मूल चरित्र को परिभाषित करती है। यह यात्रा उस स्थान तक जाएगी, जहां गुरु तेगबहादुर जी ने सनातन धर्म की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया था।उन्होंने कहा कि औरंगजेब के काल में तिलक, जनेऊ और धर्म को समाप्त करने की साजिशें रची जा रही थीं। ऐसे समय में गुरु तेगबहादुर जी ने सबसे पहले प्रतिकार किया। उनके साथ भाई सतिदास, भाई मतिदास और भाई दयाला जी पर अमानवीय अत्याचार किए गए, उन्हें धर्म परिवर्तन के लिए डराया-धमकाया गया, पर वे अपने पथ से नहीं डिगे। अंततः उन्होंने शहादत दी और आने वाली पीढ़ियों के लिए अमर प्रेरणा बन गए। मुख्यमंत्री ने कहा कि यही बलिदान की परंपरा आज के मजबूत भारत की नींव है।मुख्यमंत्री ने कहा कि आज भारत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है और इसकी बुनियाद उन बलिदानों पर टिकी है जो धर्म, सत्य और न्याय के लिए दिए गए। उन्होंने कहा कि सिख गुरुओं का इतिहास पूरे देश के लिए मार्गदर्शक है, जो बताता है कि सत्य को कोई मिटा नहीं सकता।मुख्यमंत्री ने कहा कि यह सन्देश यात्रा हमें यह याद दिलाती है कि गुरुओं ने जो त्याग और बलिदान दिए, वे केवल इतिहास नहीं, बल्कि हमारे सामाजिक व नैतिक मूल्यों की जीवंत परंपरा हैं। आज जब कुछ ताकतें धर्मांतरण और सामाजिक फूट डालने की कोशिश कर रही हैं, तो हम सबका दायित्व है कि उन कोशिशों को विफल करें और गुरुओं की प्रेरणा से समाज को जोड़ें। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश और दिल्ली की गुरुद्वारा प्रबन्धक समितियां मिलकर राष्ट्रहित में कार्य कर रही हैं, और जब हम एकजुट होकर कोई आवाज उठाते हैं, तो वह राष्ट्रीय स्तर पर असर दिखाती है।मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि पूर्व में उनके आवास पर गुरु नानक देव जी के 550वें प्रकाश पर्व के उपलक्ष्य में शबद-कीर्तन का आयोजन किया गया था। इसके साथ ही वीर बाल दिवस जैसे कई कार्यक्रम भी राज्य स्तर पर आयोजित किए गए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी द्वारा 26 दिसंबर को 'वीर बाल दिवस' के रूप में घोषित करना, भारत की भावी पीढ़ियों को इतिहास से जोड़ने की एक ऐतिहासिक पहल है।मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यह सन्देश यात्रा एक शुरुआत है, जो भारत की करोड़ों जनता के मन में श्रद्धा, ऊर्जा और प्रेरणा का स्रोत बनेगी। यह यात्रा केवल दिल्ली नहीं जाएगी, बल्कि हर भारतीय के हृदय में गुरु तेगबहादुर जी की अमर गाथा को जीवित कर देगी।इस मौके पर कृषि राज्य मंत्री बलदेव सिंह ओलख, विभिन्न गुरुद्वारा प्रबन्ध समितियों के पदाधिकारी और अनेक गणमान्य नागरिक भी उपस्थित रहे।

शादी का झांसा देकर यौन शोषण करने का आरोपित गिरफ्तार

लखनऊ। सुशांत गोल्फ सिटी पुलिस ने युवती को शादी का झांसा देकर उसके शारीरिक सम्बन्ध बनाने व जान से मारने की धमकी देने वाले आरोपित को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। पुलिस के अनुसार 29 जून को एक युवती ने लिखित शिकायत की थी कि कोरारी पोस्ट मंगटा थाना गजनेर जनपद कानपुर देहात के रहने वाले कौशल सिंह ने शादी का झांसा देकर उससे शारीरिक सम्बन्ध बनाए।शादी की बात करने पर पीड़ति गाली गलौज करने के साथ उसे जान से मारने की धमकी दी।जिसपर पुलिस मुकदमा पंजीकृत कर आरोपित की तलाश कर रही थी लेकिन वह फरार चल रहा था।जिसे पुलिस ने शुक्रवार को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।

क्लब हाउस में बिल्डर ने पूजा करने से रोका तो आवंटियों ने किया प्रदर्शन

आर्यावर्त क्रांति ब्यूरो

लखनऊ। सुशान्त गोल्फ सिटी स्थित चंद्रा पैनोरमा अपार्टमेंट में शनिवार को बिल्डर द्वारा आवंटी को क्लब हाउस में पूजा करने से मना किया गया। जिससे आवंटी भड़क गए। जिसके बाद एकत्र होकर बिल्डर के खिलाफ धरना प्रदर्शन करने लगे। बिल्डर ने आवंटियों की भीड़ देखकर पुलिस बुला ली। मौके पर पहुंची पुलिस ने लोगो को समझा बुझा कर मामला शांत कराया।

चंद्रा पैनोरमा के फ्लैट्स के आवंटियों का आरोप है कि बिल्डर आलोक चंद्रा द्वारा फ्लैट्स के आवंटियों से वर्ड क्लास का क्लब हाउस बनाने के नाम पर 7 करोड़ 3 लाख रुपये लिए गए लेकिन क्लब हाउस न बनाकर बेसमेंट के एक हिस्से को क्लब हाउस बना दिया गया। यही नही आवंटियों का आरोप है कि बिल्डर ने क्लब हाउस यूज करने के लिये पहले 11 हजार 800 रुपये जमा करने को कहा। जिस पर आवंटी ने आरडब्ल्यूए की अध्यक्ष डिम्पी बजपेई से की। जिसके बाद सभी पदाधिकारी व आवंटी एकत्र होकर बिल्डर के प्रदर्शन करने लगे। आवंटियों को एकत्र होता देख बिल्डर ने पुलिस बुला ली। सूचना पर पहुंची पुलिस ने आवंटियों को समझा बुझा कर मामला शांत कराया। आरडब्ल्यूए की अध्यक्ष डिम्पी बाजपेई का आरोप है कि बिल्डर ने वादे के अनुसार कोई काम नही किया। उनका आरोप है कि बिल्डर ने क्लब हाउस के निर्माण के लिए आवंटियों से लिये गए 7 करोड तीन लाख रुपयों से क्लब हाउस न बना कर उसे हजम कर गये, और बेसमेंट को क्लब हाउस बना दिया। आवंटन के दौरान बताया था कि क्लब हाउस में वर्ड क्लास का होगा लेकिन बेसमेंट में समा कर रह गया।

बहराइच में दिवंगत सासू माँ को श्रद्धांजलि देते हुए उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने व्यक्त की संवेदनाएं

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने शनिवार को जनपद बहराइच में माननीय विधायक एवं पूर्व राज्यमंत्री अनुपमा जायसवाल के निज आवास पर पहुंचकर उनकी दिवंगत सासू माँ के छायाचित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। उप मुख्यमंत्री ने शोकसंतप्त परिवार से भेंट कर गहरी संवेदनाएं व्यक्त कीं और प्रभु श्रीराम से दिवंगत की आत्मा की शांति तथा परिजनों को धैर्य और संबल प्रदान करने की प्रार्थना की।इस अवसर पर मीडिया से बातचीत करते हुए उप मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में देश और प्रदेश हर क्षेत्र में प्रगति की नई ऊँचाइयों को छू रहा है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत सामरिक शक्ति बनने के साथ-साथ अर्थव्यवस्था के मामले में भी तेजी से आगे बढ़ रहा है।

बहराइच में उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने दी श्रद्धांजलि, जनप्रतिनिधियों व नागरिकों से की मुलाकात

आर्यावर्त क्रांति ब्यूरो

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य शनिवार को जनपद बहराइच पहुंचे, जहां उन्होंने सदर विधायक एवं पूर्व राज्यमंत्री अनुपमा जायसवाल के निज आवास पर जाकर उनकी दिवंगत सासू मां के छायाचित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। उन्होंने शोकसंतप्त परिवार से भेंट कर अपनी गहरी संवेदना प्रकट की और प्रभु श्रीराम से दिवंगत आत्मा की शांति तथा परिजनों को संबल प्रदान करने की प्रार्थना की।श्रद्धांजलि अर्पित करने के उपरांत उपमुख्यमंत्री ने मीडिया से बातचीत में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में देश और प्रदेश हर क्षेत्र में तेजी से प्रगति कर रहा है। उन्होंने बताया कि भारत आज सामरिक दृष्टि से मजबूत हो रहा है और आर्थिक मोर्चे पर भी नई ऊंचाइयों को छू रहा है।उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश नित नए आयाम स्थापित कर रहा है और 25 करोड़ से अधिक लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं। उपमुख्यमंत्री ने प्रदेश की कानून व्यवस्था का जिक्र करते हुए कहा कि अपराधियों और माफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है, जिससे प्रदेश में शांति और सुशासन की स्थिति बनी रहे और विकास को गति मिले।श्रावण मास में चल रही कांवड़ यात्रा का उल्लेख करते हुए उपमुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश सरकार श्रद्धालुओं के लिए समुचित व्यवस्था कर रही है। कांवड़ यात्रा मार्गों पर पुष्पवर्षा और अन्य आवश्यक व्यवस्थाएं कराई जा रही हैं ताकि भक्तों को कोई असुविधा न हो।उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के मूलमंत्र के साथ बिना किसी भेदभाव के कार्य कर रही है और पात्र व्यक्तियों को सरकारी योजनाओं का पूरा लाभ मिल रहा है।इस अवसर पर बहराइच सांसद आनंद कुमार गौड़, विधान परिषद सदस्य डॉ. प्रज्ञा त्रिपाठी, विधायक पयागपुर सुभाष त्रिपाठी, विधायक नानपारा राम निवास वर्मा, विधायक श्रावस्ती रामफेरन पांडेय, पूर्व मंत्री मुकुट बिहारी वर्मा, कमलेश मिश्रा, बृजेश पांडेय, जिलाधिकारी मोनिका रानी, पुलिस अधीक्षक रामनयन सिंह, मुख्य विकास अधिकारी मुकेश चंद्र, अपर जिलाधिकारी गौरव रंजन श्रीवास्तव, अपर पुलिस अधीक्षक (नगर) रामानंद कुशवाहा, अपर पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) दुर्गा प्रसाद, मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ. संजय कुमार, डीडीओ राज कुमार सहित बड़ी संख्या में गणमान्य नागरिक, अधिकारी और जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे।

हज़रतगंज में सजी 'सुता' की शिल्प–संवेदना, अदिति जग्गी रस्तोगी के साथ लखनऊ में दस्तक

आर्यावर्त क्रांति ब्यूरो

लखनऊ। नवाबों के शहर में फ़ैशन प्रेमियों के लिए एक नई सौगात जुड़ गई है। अपनी भावनात्मक साड़ियों, बारीक दस्तकारी और भारतीय परंपरा की सुंदरता को संजोए मशहूर ब्रांड सुता ने आज हज़रतगंज स्थित आदि फ़ैशन हाउस में अपनी खास मौजूदगी दर्ज कराते हुए लखनऊ में कदम रखा।इस अवसर पर रेशम रत्न सम्मान से सम्मानित, जानी-मानी डिज़ाइनर और खादी बोर्ड की फ़ैशन सलाहकार अदिति जग्गी रस्तोगी की उपस्थिति में खादी, रेशम और चिकनकारी परिधानों की एक आकर्षक प्रदर्शनी आयोजित की गई। भारतीय वस्त्रों के वैश्वीकरण को समर्पित अदिति रस्तोगी और सुता ब्रांड के इस साझा प्रयास ने लखनऊ के फ़ैशन परिदृश्य को नया आयाम दिया।12 जुलाई को आयोजित इस कार्यक्रम में लखनऊ के फ़ैशन प्रेमियों ने सुता के बहुचर्चित रेडी-टू-वियर क्लासिक्स, हाथ से बने ब्लाउज़ और समकालीन ड्रेसेज़ को क़रीब से देखा और सराहा। समकालीन फ़ैशन को पारंपरिक कलात्मकता से जोड़ने वाला यह ब्रांड शहर के लिए एक नया अनुभव लेकर आया है।सुता की सह-संस्थापक सुजाता बिस्वास और तान्या बिस्वास ने कहा, "हमने हमेशा प्यार से बुनी कहानियों में विश्वास किया है, और लखनऊ अपने तहज़ीब और शालीनता के कारण हमें घर जैसा लगता है। अदिति जग्गी रस्तोगी के आदि फ़ैशन हाउस के साथ यह सहयोग हमारे विज़न के लिए एकदम सही मेल है, और हम लखनऊ में अपने सुता परिवार से मिलकर बेहद उत्साहित हैं।"

चंद्रशेखर आजाद की चेतावनी, 'मुसलमानों को शूद्र बनाने का हो रहा प्रयास'

आर्यावर्त क्रांति ब्यूरो

लखनऊ। आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने शनिवार को राजधानी में आयोजित 'मुस्लिम संवादः समस्या और समाधान' कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश की बीजेपी सरकार पर तीखा हमला बोला है। राजधानी के अटल बिहारी वाजपेयी साइंटिफिक कन्वेंशन सेंटर में आयोजित इस कार्यक्रम में उन्होंने मुसलमानों, अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्गों के खिलाफ हो रहे अन्याय को उजागर करते हुए संवैधानिक मूल्यों की रक्षा का आह्वान किया। चंद्रशेखर ने कहा, 'मुसलमानों को शूद्र बनाने का प्रयास हो रहा है। उन्होंने कहा कि आज प्रदेश में मुसलमानों की दुकानें बंद कराई जा रही है, यह संविधान का खुला उल्लंघन है। उन्होंने कहा कि हर जख्म का हिसाब होगा।₹ उन्होंने मुस्लिम समाज से अपील की, 'इस लड़ाई में आप हमारे साथ खड़े हो जाइए, और जब जरूरत पड़े, आगे बढ़कर आवाज उठाइए।' उन्होंने बीजेपी की नकारात्मक राजनीति को देश के लिए हानिकारक बताते हुए कहा, ₹अगर मुसलमान बीजेपी को वोट देने लगें, तो यह पार्टी सबसे निचले स्तर पर पहुंच जाएगी। उन्होंने कहा कि सकारात्मक राजनीति ही देश को बचा सकती है।' उन्होंने पिछड़े वर्गों के साथ हो रहे अत्याचारों, जैसे कथा करने पर चोटियां काटने की घटनाओं का जिक्र किया और कहा, 'शोषण किसी एक वर्ग तक सीमित नहीं। अगड़ा हो या पिछड़ा, जो सरकार की सोच के साथ नहीं, उसे निशाना बनाया जा रहा है।' चंद्रशेखर ने पार्टी के संविधान की जानकारी देते हुए कहा है कि यहां बराबरी का अधिकार है। कहा कि, ₹हमारी पार्टी में अनुसूचित जाति, पिछड़ा और मुस्लिम को समान हक दिया गया है। आज की चर्चा को हम चुनावी मैनिफेस्टो में शामिल करेंगे, ताकि उत्तर प्रदेश के स्कूल, कॉलेज, किसान, नौजवान और पिछड़ों का भविष्य सुरक्षित हो।' उन्होंने चेतावनी दी, 'सत्ता लोगों के हक छीन सकती है, लेकिन लोकतंत्र में वोट ही शासन तय करता है। गुलाम भारत में राजा रानी के पेट से पैदा होता था, लेकिन आजाद भारत में भी कुछ लोग राजतंत्र की तरह जी रहे हैं। उन्होंने 'इस संवाद ने न केवल सामाजिक अन्याय के खिलाफ एकजुटता का संदेश दिया, बल्कि आगामी चुनावों में संविधान की रक्षा और वंचित वर्गों के हक के लिए संघर्ष का आह्वान भी किया। चंद्रशेखर की यह हुंकार सत्ता को चुनौती देने का स्पष्ट संदेश दे रही है।

तेज बारिश में रोड बनी तालाब

आर्यावर्त क्रांति ब्यूरो

लखनऊ। शनिवार की सुबह हुई तेज बारिश से सुशांत गोल्फ सिटी क्षेत्र में अहिमामऊ के पास सुल्तानपुर राजमार्ग पर भारी जलभराव हो गया जिससे उधर से निकलने वालों को काफी दिक्कतें उठानी पड़ी

शनिवार की सुबह हुई जोरदार बारिश ने जहां एक ओर धान की रोपाई करने वाले किसानों व गर्मी से परेशान लोगों को गर्मी से राहत दिलाई वहीं दूसरी ओर अहिमामऊ के पास सुल्तानपुर रोड तालाब बन गई जिससे उधर से निकलने वालों को काफी दिक्कतें उठानी पड़ी।बड़ी बड़ी गाड़ियां आधी आधी पानी मे डूबी नजर आई वहीं बाइक सवारों को कहीं कहीं पानी मे पैर रखना पड़ा।बारिश से तालाब बनी सुल्तानपुर रोड पर बारिश बंद होने के काफी देर बाद तक राहगीरों को जलभराव के बीच से होकर गुजरना पड़ा।जिससे कई गाडियां पानी में बंद भी हो गई।यहां की स्थिति यह पहली बार नहीं हुई है बल्कि जैसे ही थोड़ी बारिश होते ही यहाँ सड़क पर दोनों ओर जलभराव हो जाता है।आसपास के व्यापारियों के अनुसार इसकी वजह सुल्तानपुर राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण में मानक को दरकिनार कर नाला बनाया गया है क्योंकि शहीद पथ व सीजी सिटी दोनों तरफ की ढाल अहमामऊ की तरफ कर दी गई है जिससे यहां भारी जलभराव हो जाता है। जिसकी एनएच के जिम्मेदारों से कई बार शिकायत भी की जा चुकी है लेकिन समस्या जस की तस बनी हुई है और इसका खमियाजा राहगीरों को भुगतना पड़ रहा है।

लुलु मॉल की तीसरी वर्षगांठ पर 'हैट्रिक ऑफ हैप्पीनेस', लखनऊवासियों संग बांटी खुशियों की सौगात

आर्यावर्त क्रांति ब्यूरो

लखनऊ। लखनऊ के सबसे बड़े और लोकप्रिय शॉपिंग गंतव्य लुलु मॉल ने अपने तीन वर्ष पूर्ण होने पर 'हैट्रिक ऑफ हैप्पीनेस' के नाम से भव्य उत्सव का आयोजन किया। शहरवासियों के लिए यह आयोजन न केवल मनोरंजन और खरीदारी का अवसर बना, बल्कि मॉल ने इस मौके को खुशियों की सौगात में बदलते हुए एक और यादगार अध्याय जोड़ दिया।तीसरी वर्षगांठ के अवसर पर लुलु मॉल ने अपने लॉयल ग्राहकों के लिए विशेष इनाम योजना की भी घोषणा की। 20 जुलाई तक ₹5000 या उससे अधिक की खरीदारी करने वाले ग्राहकों को लकी ड्रा के माध्यम से महिंद्रा एक्सयूवी या टीवीएस अपाचे आरटीआर जीतने का अवसर दिया जा रहा है, जिससे ग्राहक वर्ग में विशेष उत्साह देखा गया।हर वर्ष की तरह इस बार भी मॉल में 'लुलु रिटेल अवॉर्ड्स' का आयोजन किया गया, जिसमें 300 से अधिक नामचीन ब्रांड्स ने 29 विभिन्न श्रेणियों में भाग लिया। ग्राहकों ने अपने पसंदीदा ब्रांड्स को लेकर उत्साहपूर्वक वोटिंग की और अंत में चयनित ब्रांड्स को ट्रॉफी प्रदान कर सम्मानित किया गया। यह आयोजन मॉल और ग्राहकों के बीच मजबूत संबंधों का प्रतीक बना, साथ ही रिटेल क्षेत्र में उत्कृष्टता और नवाचार को प्रोत्साहित करने का माध्यम भी।इस समारोह में 'बेस्ट एंकर ब्रांड' के रूप में लुलु हाइपरमार्केट को सम्मानित किया गया। 'ब्यूटी एंड वेलनेस ब्रांड' की श्रेणी में फॉरेस्ट एसेंशियल्स, 'बेस्ट इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांड' के रूप में सैमसंग, 'बेस्ट वुमेन्स फैशन ब्रांड' के रूप में ओनली (ONLY) और 'बेस्ट मेंस फैशन ब्रांड' के रूप में जैक एंड जोन्स (Jack & Jones) को अवॉर्ड से नवाजा गया। वहीं 'बेस्ट रेस्टोरेंट ब्रांड' की श्रेणी में कैफे दिल्ली हाइट्स को सम्मान प्राप्त हुआ। अन्य श्रेणियों में भी कई ब्रांड्स को उनकी श्रेष्ठता के आधार पर सम्मान प्रदान किया गया।तीन वर्षों में लुलु मॉल लखनऊवासियों की पहली पसंद बन चुका है। 300 से अधिक अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय ब्रांड्स के साथ इसने फैशन, लाइफस्टाइल और पारिवारिक मनोरंजन के क्षेत्र में एक नई ऊंचाई हासिल की है। लुलु हाइपरमार्केट जहां शहर के हर घर की जरूरतों का हिस्सा बन चुका है, वहीं बच्चों के लिए बना लुलु फनटूरा लखनऊ का सबसे बड़ा और अनूठा गेमिंग व प्ले ज़ोन बन गया है।इस अवसर पर मॉल प्रबंधन ने सभी ग्राहकों, ब्रांड्स और सहयोगियों के प्रति आभार प्रकट करते हुए कहा कि लुलु मॉल की तीन वर्षों की यह शानदार यात्रा सभी के सहयोग और विश्वास से संभव हो पाई है। मॉल प्रबंधन ने यह भी विश्वास जताया कि आने वाले वर्षों में लुलु मॉल लखनऊ की पसंद और पहचान बना रहेगा तथा ग्राहकों की अपेक्षाओं पर पूरी निष्ठा और प्रतिबद्धता के साथ खरा उतरता रहेगा।

लखनऊ में नगर निगम का पालतू कुत्तों पर सख्त रुख, बिना लाइसेंस वालों से वसूले गए जुर्माने

आर्यावर्त संवाददाता

लखनऊ। नगर निगम लखनऊ द्वारा पालतू कुत्तों के लाइसेंस चेकिंग के लिए विशेष अभियान चलाया गया। नगर आयुक्त गौरव कुमार के निर्देश पर यह अभियान पशु कल्याण अधिकारी डॉ. अभिनव वर्मा के नेतृत्व में प्रातः 6:30 बजे से जोन-3 के सेक्टर एल, एम, एन, ओ सहित अन्य क्षेत्रों में चलाया गया।अभियान के दौरान प्रवर्तन दल और डॉग कैचिंग स्क्वॉड के साथ अधिकारी राजेश उपाध्याय, शिवेक, मनोज सिंह, रामकुमार और अभिनव भारती भी मौजूद रहे। नगर निगम की इस सख्ती का असर यह देखने को मिला कि कई लोग अपने पालतू कुत्तों को लेकर मौके से भागते नजर आए और कुछ ने टीम को प्रभावित करने का प्रयास भी किया। ऐसे सभी लोगों की पहचान कर ली गई है, जिनके खिलाफ नोटिस जारी किए जाएंगे और संबंधित थाना अध्यक्ष को इसकी प्रति आवश्यक कार्यवाही के लिए भेजी जाएगी।अभियान के दौरान चार लोगों से बिना लाइसेंस कुत्ते पालने पर कुल ₹20,000 का जुर्माना वसूला गया, जबकि मौके पर दो नए लाइसेंस भी बनाए गए। कुल ₹22,000 की राशि नगर निगम के खाते में जमा कराई गई। वहीं, बिना लाइसेंस पकड़े गए दो पोमेरियन और एक पुग कुत्ते को जुर्माना भरने के बाद छोड़ा गया।बारिश और अभियान की आशंका के कारण बड़ी संख्या में लोग अपने कुत्तों को टहलाने नहीं निकले, हालांकि कुछ लोग लाइसेंस और वैक्सीनेशन कार्ड के साथ नियमों का पालन करते हुए मिले।नगर निगम के आंकड़ों के अनुसार, लखनऊ नगर निगम क्षेत्र में पालतू कुत्तों की अनुमानित संख्या लगभग 10,000 है। पालतू कुत्तों के लिए लाइसेंस केवल रैबीज वैक्सीनेशन प्रमाणपत्र और श्वान नियंत्रण उपविधि 2003 के अंतर्गत शपथ पत्र जमा करने के बाद ही जारी किया जाता है। इच्छुक नागरिक नगर निगम की वेबसाइट lmc.up.nic.in के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं या किसी कार्यदिवस पर लालबाग स्थित पशु कल्याण अधिकारी कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं।लाइसेंस से जुड़ी जानकारी के लिए संपर्क सूत्र उपलब्ध कराए गए हैं: जयंत सिंह – 9511156792, अफसर अली – 9721095021।पशु कल्याण अधिकारी डॉ. अभिनव वर्मा ने पालतू कुत्ते पालने वालों से अपील की है कि वे अनिवार्य रूप से अपने कुत्तों का लाइसेंस बनवाएं, ताकि जुर्माने से बचा जा सके। साथ ही उन्होंने आग्रह किया कि कुत्ते को टहलाते समय माउथ गार्ड और स्कूप का प्रयोग अवश्य करें। नगर निगम का यह अभियान आगे भी नियमित रूप से जारी रहेगा।

बिहार चुनावों में महिलाओं पर दांव के निहितार्थ

बिहार में इस साल अक्टूबर-नवंबर में विधानसभा चुनाव होने हैं। चुनाव आयोग ने अभी तक मतदान की तारीखों की घोषणा नहीं की है, लेकिन राज्य में राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। विभिन्न राजनीतिक दल लुभावनी घोषणाएं कर रहे हैं, नये-नये मुद्दों को उछाला जा रहा है। गोपाल खेमका हत्याकांड हो या तंत्र मंत्र के चलते एक ही परिवार के पांच लोगों को जला देने की त्रासद घटना- नीतीश कुमार पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले मतदाता सूचियों के विशेष सघन पुनरीक्षण अभियान पर संदेह के सवालों के साथ मुखर विपक्षी दल इसके खिलाफ राजनीतिक लड़ाई के साथ ही कानून विकल्पों पर भी गंभीरता से विचार कर रहे हैं। इस बीच, एनडीए की सहयोगी लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के नेता चिराग पासवान ने एनडीए से दूरी बनाते हुए बिहार की सभी 243 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का संकेत देकर सियासी परिदृश्य को दिलचस्प बना दिया है। इन्हीं परिदृश्यों के बीच बिहार सरकार ने सरकारी नौकरियों में स्थानीय महिलाओं के लिए 35 प्रतिशत सीटें आरक्षित करने के फैसला लेकर चुनावी सरगर्मियों को एक नया मोड़ दे दिया है। बिहार सरकार का यह निर्णय केवल एक चुनावी रणनीति भर नहीं, बल्कि एक गहरे सामाजिक परिवर्तन का संकेतक भी है। तय है कि इस बार के बिहार चुनाव के काफी दिलचस्प एवं हंगामेदार होंगे।

सरकारी नौकरियों में स्थानीय महिलाओं के लिए 35 प्रतिशत आरक्षण के गहरे निहितार्थ हैं। एनडीए की नीतिश सरकार ने स्थानीय महिलाओं को प्राथमिकता देने एवं उनके लिए सरकारी रोजगार उपलब्ध कराने के इस ब्रह्मास्त्र को दाग कर चुनावी समीकरण अपने पक्ष में कर लिये हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसे "महिला सशक्तिकरण का राजनीतिक समाधान" बताया, क्योंकि राज्य की महिलाएँ कई चुनावों में निर्णायक भूमिका निभा रही हैं। पिछली लोकसभा चुनाव में महिलाओं की मतदान दर पुरुषों से कहीं अधिक रही, 59.45 प्रतिशत महिलाओं ने हिस्सा लिया जबकि पुरुष केवल 53 प्रतिशत मतदान करने पहुंचे। यह आंकड़ा दिखाता है कि चुनावी जीत में महिला मतदाता कितनी निर्णायक हो सकते हैं, साफ है, सत्ता की चाबी वहां महिलाओं ने अपने हाथों में ले ली है और वे धार्मिक व जातिगत आग्रहों से अधिक लैंगिक हितों से प्रेरित हैं। बिहार उन शुरुआती राज्यों में एक है, जिसने पंचायत और स्थानीय निकायों में आधी आबादी के लिए पचास फीसदी सीटें आरक्षित की हैं। इस कदम ने यहां की स्त्रियों में जबर्दस्त राजनीतिक जागरूकता पैदा की है। चुनावों की दशा एवं दिशा बदलने में महत्वपूर्ण एवं निर्णायक किरदार निभाने के कारण ही हरेक राजनीतिक दल महिला वर्ग को आकर्षित करने में जुट गया है। राजद-कांग्रेस-वाम दलों का महागठबंधन 'माई-बहिन मान योजना' के तहत महिलाओं को प्रतिमाह 2,500 रुपये देने का वायदा कर चुका है, तो राजद नेता तेजस्वी यादव बेरोजगारी और डोमिसाइल के मुद्दे को जोर-शोर से उठा रहे हैं। ऐसे में, नीतीश सरकार के इस नीतिगत दांव को समझा जा सकता है। जातिगत और स्थानीय समीकरण भुनाने के लिए निश्चित ही यह एक संगठित चाल है, जहां जाति और आवासीयता दोनों को आधार बनाया गया।

यह सर्वविदित तथ्य है कि भारत में शैक्षिक क्षेत्र में लैंगिक खाई लगातार सिमट रही है। बिहार की बेटियां देश के अनेक महानगरों में अपनी योग्यता और मेहनत के दम पर पहचान बना चुकी हैं। सूचना क्रांति, बढ़ती अपेक्षाओं और सामंती बंधनों के ढीले पड़ते जाने के कारण अब ग्रामीण बिहार की बेटियां भी ऊंचे सपने संजो रही हैं। हाल ही में बिहार में शिक्षकों की नियुक्ति के दौरान यह देखा गया कि देश के विभिन्न प्रदेशों की योग्य लड़कियां इंटरव्यू देने आईं, जिनमें से अनेक ने सफलता प्राप्त की और अब बिहार के सरकारी स्कूलों में अध्यापन कर रही हैं। निस्संदेह, यह एक सैद्धांतिक रूप से प्रगतिशील और समावेशी समाज का प्रतीक है, जहाँ महिलाएं सीमाओं से परे जाकर अपनी पहचान बना रही हैं। लेकिन व्यावहारिक धरातल पर देखें, तो महिला सुरक्षा, सामाजिक असमानता, आवास व पारिवारिक बाधाएं, और प्रवास की मजबूरियाँ अब भी मौजूद हैं। ऐसे में यदि सरकारें योग्य महिलाओं को उनके घर के आस-पास ही रोजगार के अवसर उपलब्ध कराएं, तो यह न केवल महिला सशक्तिकरण की दिशा में सार्थक कदम होगा, बल्कि सामाजिक संरचना में स्थिरता और पारिवारिक सहूलियत का भी कारण बनेगा। यही कारण है कि नीतीश कुमार सरकार महिला मतदाताओं को लुभाने के लिए एक के बाद एक योजनाएं ला रही है। साइकिल योजना, पोशाक योजना, कन्या उत्थान योजना, वृद्धावस्था पेंशन में वृद्धि, पिंक टॉयलेट, महिला पुलिस भर्ती में आरक्षण जैसे कई कदम इस सिलसिले में पहले ही उठाए जा चुके हैं। यह मान्यता कि बेटियां अब सिर्फ अपने घरों की शोभा नहीं, बल्कि राष्ट्र निर्माण की भागीदार हैं, नीति निर्माण में स्पष्ट झलकने लगा है।

बिहार में मतदाता पहचान पत्र से जुड़े सुलगते सवालों का जवाब आखिर देगा कौन?

ऐसे में सुलगता सवाल है कि जिस आधार पर आप लोगों को सरकारी धनराशि से सहूलियत देते हैं, उसी महत्वपूर्ण 'पहचान आधार' को आप एसआईआर में खारिज कैसे कर सकते हैं।

कमलेश पांडेय

बिहार में इसी वर्ष अक्टूबर-नवंबर माह में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में वहां पर चुनाव आयोग के द्वारा जारी स्पेशल इंटेंसिव रिविजन यानी एसआईआर पर पक्ष-विपक्ष आमने सामने है और मामला मीडिया माध्यम से आगे बढ़कर सर्वोच्च न्यायालय की दहलीज तक पहुंच चुका है। इसलिए उम्मीद है कि देर आयद, दुरुस्त आयद करते हुए न्यायालय ऐसे दिशा निर्देश जारी करेगा कि भविष्य में राजनेताओं और प्रशासनिक अधिकारियों की सांठगांठ से चलने वाले मतदाता सूची सम्बन्धी खेल पर पूर्ण विराम लग सके।

बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को बिहार में वोटर लिस्ट की समीक्षा के लिए आधार, राशन और वोटर कार्ड को भी मान्यता देने का सुझाव देकर न केवल आम लोगों की मुश्किल हल करने की कोशिश की है, बल्कि ऐसा करने से इसकी प्रक्रिया भी ज्यादा आसान होगी और विभिन्न आशंकाओं को कम करने में मदद मिलेगी। इस बात में कोई दो राय नहीं कि फर्जी नाम मतदाता सूची में नहीं होने चाहिए। इसके अलावा, किसी भी विदेशी व्यक्ति का नाम भी मतदाता सूची में नहीं होना चाहिए, अन्यथा मतदाता सूची की विश्वसनीयता सवालों के कठघरे में रहेगी।

कोर्ट का सही मानना है कि ऐसे एसआईआर अभियानों के दौरान आयोग का जोर ज्यादा से ज्यादा नाम वोटर लिस्ट से निकालने के बजाय, इस पर होना चाहिए कि एक भी नागरिक चुनावी प्रक्रिया में शामिल होने से वंचित न रह जाए। जहां तक इसे लेकर संशय की स्थिति है तो आधार, राशन कार्ड या जॉब कार्ड को मान्य दस्तावेजों की लिस्ट से बाहर रखने के कारण बड़ी आबादी के सामने संकट खड़ा हो गया है। ऐसे में सुलगता सवाल है कि जिस आधार पर आप लोगों को सरकारी धनराशि से सहूलियत देते हैं, उसी महत्वपूर्ण 'पहचान आधार' को आप एसआईआर में खारिज कैसे कर सकते हैं। आपके ऐसा करने से यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि स्थानीय जनप्रतिनिधियों और प्रशासनिक अधिकारियों की मिलीभगत से जो संस्थागत लूट चल रही है, उसकी अब सोशल ऑडिट जरूरी है, क्योंकि इस मामले में पक्ष-विपक्ष सभी शामिल हैं। सच कहूं तो इससे भारत के उन मूल निवासियों को क्षति हो रही है जिनका देश की सरकार और संसाधनों पर पहला अधिकार होना चाहिए।

हमारा आशय उस हिन्दू वर्ग से है जो धार्मिक आधार पर राष्ट्र विभाजन के बाद भी राजनीतिक व संवैधानिक षड्यंत्र का शिकार होता आया है। जब पाकिस्तान व बंगलादेश इस्लामीकरण की राह पर बढ़ रहे हैं तो भारत की धर्मनिरपेक्षता हिंदुओं के साथ बेमानी प्रतीत हो रही है। आलम यह है कि मुस्लिम नेता पाकिस्तान व बंगलादेश से मुसलमानों को बुलाकर यहां बसा रहे हैं और उन्हें सरकारी पहचान पत्र दिलवाने में मदद कर रहे हैं। इस प्रवृत्ति को रोकने-टोकने की प्रशासनिक विफलता या मिलीभगत से कई सवाल पैदा हो रहे हैं, जो हिंदुओं के दूरगामी हित के लिए से चेतावनी दे रहे हैं।

ऐसे में एसआईआर की जरूरत है। साथ ही, सरकारी पहचान पत्र बनवाने और उससे लाभान्वित होने के पूरे खेल की समीक्षा हो और जिम्मेदार अधिकारियों, नेताओं और उनके दलों के खिलाफ ऐसी कड़ी कार्रवाई हो, कि उनके चुनाव लड़ने पर आजीवन प्रतिबंध लगे, राजनीतिक दलों की मान्यता समाप्त हो और अधिकारियों-कर्मचारियों की बर्खास्तगी की जाए। क्योंकि ये लोग भारत के भविष्य से खिलवाड़ कर रहे हैं। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, केवल किशनगंज जिले में एक हफ्ते के भीतर निवास प्रमाण पत्र के लिए दो लाख से ज्यादा आवेदन आ चुके हैं। कई जगह घर-घर जाकर इंयुमरेशन फॉर्म्स (Enumeration Forms) बांट रहे कर्मियों ने लोगों से कहा है कि वे आधारकार्ड की कॉपी ही जमा करा दें। लिहाजा ऐसे कंफ्यूजन से बेहतर है कि आयोग बीच का रास्ता निकाले। जहां तक एसआईआर के समय पर सवाल है तो शीर्ष अदालत ने स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (Special Intensive Revision) पर रोक तो नहीं लगाई, लेकिन इसके समय को लेकर जो सवाल उठाया, वह बिल्कुल वाजिब है। ऐसा इसलिए कि बिहार में इसी साल के आखिर तक विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में इतनी विस्तृत कवायद के लिए शायद उतना वक्त न मिल पाए, जितना मिलना चाहिए। लिहाजा बिहार में एसआईआर को लेकर जो असमंजस है, उसकी एक वजह इसका समय भी है। जिनके पास जरूरी दस्तावेज नहीं हैं, वे इतनी जल्दी उनका इंतजाम नहीं कर पाएंगे।

हालांकि आयोग ने कोर्ट को भरोसा दिलाया है कि किसी को भी अपनी बात रखने का मौका दिए बिना मतदाता सूची से बाहर नहीं किया जाएगा। वहीं, जहां तक नागरिकता पर फैसला का सवाल है तो बताया गया है कि इस अभियान का उद्देश्य ऐसा नहीं है। जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि यह मुद्दा लोकतंत्र की जड़ों से जुड़ा है और लोकतंत्र में सबसे अहम है लोक यानी जनता। लेकिन, चुनाव आयोग की मौजूदा प्रक्रिया में जनता को ही सबसे ज्यादा परेशानी हो रही है। यह रिवीजन जुड़ा है वोटर लिस्ट से, लेकिन मैसेज जा रहा है कि इससे नागरिकता तय होगी। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी से राहत मिलेगी कि निर्वाचन आयोग का नागरिकता से कोई लेना-देना नहीं है।

हालांकि, इतना तो तय है कि इस एसआईआर अभियान का असर अब पूरे देश पर पड़ेगा। ऐसा होना भी चाहिए। लेकिन जबतक संविधान में अमूलचूल बदलाव नहीं होगा तबतक इस प्रवृत्ति पर लगाम लगाने में मुश्किल आएगी।चूंकि यह मामला केवल बिहार तक सीमित रहने वाला नहीं है। ऐसे में दूसरे राज्यों में वोटर लिस्ट की समीक्षा किस तरह होगी, यह बिहार में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया पर निर्भर करेगा। क्योंकि अगला नम्बर पश्चिम बंगाल और असम का आएगा जहां अगले साल चुनाव होंगे। ऐसे में स्वाभाविक ही नजरें इस बात पर टिकी हैं कि सुप्रीम कोर्ट में आखिरकार इस प्रक्रिया का कैसा स्वरूप तय होता है। इसी से यह स्पष्ट हो जाएगा कि भारत के इस्लामीकरण का यह परोक्ष अभियान निकट भविष्य में थमेगा या जारी रहेगा। क्योंकि इसके तार अंतरराष्ट्रीय षड्यंत्र से जुड़े हुए हैं। अमेरिका-पाकिस्तान-चीन दशकों से इस कोशिश में जुटे हैं, क्योंकि हमारी सरकारें भी अपने वोट बैंक के लिहाज से काम करती आई हैं, भारतीय राष्ट्रवाद के हिसाब से नहीं। खासकर 15 अगस्त 1947 के बाद उतपन्न अप्रत्याशित स्थिति से!

होना तो यह चाहिए कि भारत सरकार का जनसंख्या रजिस्टर ऑनलाइन हो। उसमें स्पष्ट उल्लेख हो कि इस ग्राम या मोहल्ले का फलां व्यक्ति अब फलां जगह के लिए पलायन कर गया है। उसका एक जन्म प्रमाण पत्र बने जो पूरे देश में लागू हो। मृत्यु प्रमाण पत्र की अनिवार्यता बने।सभी दस्तावेज इसी आधार पर बनें और पूरे देश में लागू हों। बैंक भी उसी आधार पर खाता खोलें। आज राशन कार्ड, मजदूर जॉब कार्ड, आधार कार्ड की आड़ में जो संस्थागत लूट चल रही है, वह रूके। लेकिन रोकेगा कौन? जो भ्रष्ट हैं, जांच का जिम्मा उनसे लेकर अन्य को दिया जाए। सोशल ऑडिट से बेहतर कुछ नहीं हो सकता। डीएम, एसडीएम की ऐसी लापरवाहियों के लिए स्थायी जांच एजेंसी बने। उसकी रिपोर्ट राजनीतिक दांवपेंच से बाहर रहकर लागू करने का प्रावधान बने। इसलिए यक्ष प्रश्न है कि बिहार में मतदाता पहचान पत्र से जुड़े सुलगते सवालों का जवाब आखिर देगा कौन?

अजब-गजब

Wi-Fi राउटर की स्पीड बढ़ाने का ये तरीका करता है काम? तरीका का ऐसा कि लोग रह गए भौचक्के

आज के समय में अगर फोन इंसानों की जान है तो इंटरनेट उसकी आत्मा..! इसके बिना अगर देखा जाए तो फोन सिर्फ एक डिब्बा है। हालांकि आज के मॉर्डन जमाने में भी इसकी स्पीड़ को लेकर अक्सर लोगों में बहस चलती रहती है। फिलहाल इसको इसको लेकर एक मामला लोगों के बीच चर्चा में आया है। जहां एक उपाय बताया गया है, जिसकी मदद से आप अपने घर में रखे वाई-फाई राउटर की स्पीड़ को आराम से बड़ा सकता है। ये तरीका ऐसा है, जिसको लेकर फिलहाल लोगों के बीच बहस जारी है।

देखिए अगर किसी को नेट सर्फिंग करनी है तो उसका मजा हाई-स्पीड़ पर ही आता है। जिसमें वो फटाफट अपने कंटेंट को आराम से देख सकते हैं। जबकि इसको लेकर लोग-तरह की बहस भी करते हैं। अब सामने आए इस केस को ही देख लीजिए जहां ये बताया कि अगर आप अपने Wi-Fi को तीन तरफ से एल्युमिनियम फॉयल कवर करेंगे तो इससे आपके नेट की स्पीड़ की काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। इसको लेकर लोगों में अलग ही तरह की बहस छिड़ी हुई है।

इस बात को X पर @kirawontmiss नाम के यूजर ने शेयर किया है और लोगों से पूछा कि क्या सच में ये चीज काम करती है? इस पोस्ट को अब तक 3 करोड़ से ज्यादा लोग देख चुके हैं। बता दें कि ये Wi-Fi राउटर की स्पीड बढ़ाने का सही तरीका नहीं है क्योंकि राउटर के आसपास एल्युमिनियम फॉयल लगाने से सिंग्रल एक ही दिशा में मजबूत हो जाता है और लोगों को लगता है कि इससे WIFI की स्पीड़ तेज हो गई है। जबकि ऐसा होता कुछ नहीं है।

इस चीज को देखने के बाद कई लोगों ने इस पर कमेंट कर अपनी प्रतिक्रिया दिए जा रहे हैं। एक यूजर ने लिखा कि मुझे नहीं लगता कि ये तरीका सच में काम करता होगा। वहीं दूसरे ने लिखा कि कुछ भी कहो इस तरीके को मैं भी यूज किया हूं ये काम अच्छा करता है। एक अन्य ने लिखा कि वैसे, रेडियो वेव्स को तकनीकी रूप से एल्युमिनियम फॉइल से परावर्तित किया जा सकता है।

ब्लॉग

17 देशों की संसदों में संबोधन, 27 देशों से सर्वोच्च सम्मान, विश्व मंच पर मोदी का जादू बरकरार

नीरज कुमार दुबे

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतरराष्ट्रीय कूटनीति और वैश्विक नेतृत्व के क्षेत्र में भारत को एक नई ऊँचाई पर पहुंचा दिया है। जहां एक ओर उन्होंने अब तक 17 देशों की संसदों को संबोधित कर भारत की आवाज़ को विश्वमंच पर मुखर किया है, वहीं दूसरी ओर 27 देशों से प्राप्त सर्वोच्च नागरिक सम्मानों ने उन्हें दुनिया के सबसे सम्मानित और प्रभावशाली नेताओं में स्थान दिला दिया है। यह उपलब्धियाँ केवल व्यक्तिगत सम्मान नहीं, बल्कि भारत की वैश्विक स्थिति की उन्नति का प्रतिबिंब हैं।

प्रधानमंत्री मोदी का संसदों में संबोधन केवल भाषण नहीं, बल्कि रणनीतिक कूटनीति का हिस्सा है। उन्होंने विकसित और विकासशील देशों, दोनों के विधायी मंचों पर भारत की लोकतांत्रिक विरासत, आर्थिक दृष्टि और वैश्विक सहयोग की भावना को साझा किया। मोदी की ओर से अन्य देशों की संसदों में दिये गये संबोधन को याद करें तो उन्होंने 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद ऑस्ट्रेलिया, फिजी, भूटान, नेपाल की संसदों को संबोधित किया। साल 2015 में प्रधानमंत्री ने ब्रिटेन, श्रीलंका, मंगोलिया, अफगानिस्तान और मॉरीशस की संसद को संबोधित किया। साल 2016 में उन्होंने अमेरिकी कांग्रेस के संयुक्त सत्र को संबोधित किया। 2018 में प्रधानमंत्री ने युगांडा और 2019 में मालदीव की संसद में अपना संबोधन दिया। 2023 में प्रधानमंत्री मोदी ने दूसरी बार अमेरिकी कांग्रेस में अपना संबोधन दिया और इसके साथ ही वह उन कुछ चुनिंदा वैश्विक हस्तियों में शुमार हो गये जिन्हें दो बार अमेरिकी कांग्रेस को संबोधित करने का गौरव हासिल हुआ है। इसके बाद प्रधानमंत्री ने 2024 में गुयाना और 2025 में घाना, त्रिनिदाद और टोबैगो तथा नामीबिया की संसद को संबोधित किया। खास बात यह है कि 2025 में तीन देशों की संसदों में प्रधानमंत्री का संबोधन एक सप्ताह के भीतर हुआ है जोकि अपने आप में एक और कीर्तिमान है। इन सभी संबोधनों में भारत ने ग्लोबल साउथ, संयुक्त राष्ट्र सुधार, आतंकवाद विरोध, जलवायु न्याय और डिजिटल समावेशन जैसे मुद्दों पर स्पष्ट दृष्टिकोण प्रस्तुत किया।

इसके अलावा, प्रधानमंत्री को 27 देशों से मिले सर्वोच्च सम्मान पर गौर करें तो आपको बता दें कि उन्हें यूएई का ₹Order of Zayed₹, रूस का ₹Order of St. Andrew₹, अमेरिका का ₹Legion of Merit₹, फ्रांस का ₹Grand Cross of the Legion of Honour₹, सऊदी अरब का ₹King Abdulaziz Sash₹, बांग्लादेश का ₹Liberation War Honour₹ समेत अफ्रीकी और कैरिबियाई देशों से राष्ट्रीय सम्मान मिले हैं। यह दर्शाता है कि भारत की सॉफ्ट पावर, अर्थव्यवस्था, लोकतंत्र और रणनीतिक संतुलनकारी भूमिका को विश्व स्वीकार कर रहा है।

साथ ही प्रधानमंत्री मोदी की विदेश नीति पारंपरिक 'गुटनिरपेक्षता' से आगे जाकर ₹बहुध्रुवीय मित्रता₹ पर आधारित है। उन्होंने पश्चिमी शक्तियों से रिश्ते गहरे किए, लेकिन साथ ही अफ्रीका, मध्य एशिया, खाड़ी देशों और दक्षिण अमेरिका में नए रणनीतिक संबंध भी बनाए। मोदी की यह अंतरराष्ट्रीय स्वीकृति केवल एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि भारत की उभरती शक्ति, विचारधारा और नेतृत्व क्षमता की स्वीकार्यता है। उनका हर संसद में दिया गया संबोधन, हर प्राप्त सम्मान, भारत की लोकतांत्रिक आत्मा, विकासशील दृष्टिकोण और नैतिक शक्ति का प्रतीक है।

साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 17 देशों की संसदों को संबोधित करना और 27 देशों से सर्वोच्च सम्मान प्राप्त करना, भारतीय विदेश नीति के इतिहास में एक अभूतपूर्व अध्याय है। यह दर्शाता है कि आज का भारत केवल सुनने वाला नहीं, बल्कि दुनिया को दिशा देने वाला देश बन चुका है। यह उपलब्धि भारतवासियों के आत्मविश्वास, आकांक्षाओं और अंतरराष्ट्रीय भूमिका को सशक्त करती है।

इसके अलावा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विश्व दौरों की चर्चा प्रायः उनकी रणनीतिक कूटनीति, वैश्विक नेतृत्व और द्विपक्षीय समझौतों के संदर्भ में होती है, किंतु इन यात्राओं में एक और विशेष पक्ष होता है जो चुपचाप भारत की आत्मा को विश्व के सामने प्रस्तुत करता है— वह है उनके द्वारा चयनित सांस्कृतिक उपहार। हम आपको बता दें कि हर दौरे में प्रधानमंत्री मोदी जिन विशिष्ट हस्तशिल्पों, कलाकृतियों और प्रतीकों को उपहार स्वरूप ले जाते हैं, वे केवल शिष्टाचार नहीं, बल्कि भारत की समृद्ध परंपरा, बहुरंगी संस्कृति और आत्मनिर्भर कलात्मकता का परिचायक होते हैं। यह सांस्कृतिक कूटनीति भारत की सॉफ्ट पावर को सशक्त करने में निर्णायक भूमिका निभा रही है।

हम आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी जिन वस्तुओं को विदेशी राष्ट्राध्यक्षों को भेंट करते हैं, वे भारत के अलग-अलग राज्यों, जनजातियों, परंपराओं और शिल्प कलाओं का प्रतिनिधित्व करती हैं। प्रधानमंत्री मोदी के उपहार केवल भारत की कलाओं का प्रदर्शन नहीं, बल्कि संवाद का माध्यम भी हैं। प्रधानमंत्री के उपहार दर्शाते हैं कि भारत केवल तकनीक और व्यापार का केंद्र नहीं, बल्कि हजारों वर्षों पुरानी सभ्यता का जीवंत प्रतिनिधि है। इन उपहारों के चर्चित होने से संबंधित हस्तशिल्प की मांग और मूल्य दोनों बढ़ते हैं। इसके अलावा, 'मेक इन इंडिया' और 'वोकल फॉर लोकल' की नीतियों को सांस्कृतिक स्तर पर मजबूती मिलती है।

प्रधानमंत्री मोदी और प्रवासी भारतीय समुदाय

इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी किसी देश की यात्रा पर जाते हैं, तो उनकी पहली प्राथमिकता होती है— वहाँ बसे भारतीय समुदाय से संवाद। यह मुलाकातें केवल भावनात्मक संबंधों का प्रदर्शन नहीं बल्कि नागरिक जुड़ाव का शक्तिशाली प्रतीक बन चुकी हैं। प्रवासी भारतीयों द्वारा अपने सांस्कृतिक प्रदर्शन, लोककला, संगीत और पारंपरिक वेशभूषा के माध्यम से जो दृश्य निर्मित होता है, वह विश्व के सामने भारत की एकता में विविधता और सजीव परंपरा का संदेश देता है।

प्रधानमंत्री मोदी जब इन समुदायों से मिलते हैं, तो वह यह स्पष्ट करते हैं कि वे भारत के गौरव के वाहक हैं, वे भारत और दुनिया के बीच सांस्कृतिक पुल हैं और वे भारत की सॉफ्ट पावर के सशक्त स्रोत हैं। प्रधानमंत्री मोदी की प्रत्येक विदेश यात्रा में भारतीय समुदाय द्वारा प्रस्तुत नृत्य, संगीत, भजन, पारंपरिक वेशभूषा में स्वागत, भाषणों में भारत माता की जय घोष, आदि केवल रस्म अदायगी नहीं होती, बल्कि ये दिखाते हैं कि भारत कहीं भी जाए, अपनी संस्कृति को जीवंत रखता है, भारत की परंपरा आधुनिकता के साथ सह-अस्तित्व में है और भारत की 'संवेदनशीलता' और 'संपर्क' की नीति भावनात्मक संबंधों पर आधारित है।

प्रधानमंत्री मोदी का भारतीय समुदाय से संवाद और प्रवासी भारतीयों का उनके समक्ष अपनी संस्कृति का प्रदर्शन, एक सशक्त और गहरा वैश्विक संदेश देता है कि भारत केवल एक भौगोलिक क्षेत्र नहीं, बल्कि एक संस्कार, विचार और परंपरा है, जो सीमाओं से परे जाकर भी जीवित रहती है। यह 'एक भारत, वैश्विक भारत' की संकल्पना को मजबूत करता है और दुनिया को बताता है कि भारत एक ऐसे राष्ट्र के रूप में उभर रहा है जिसकी मूल्य आधारित कूटनीति, संस्कृति आधारित संवाद और नागरिक भागीदारी आधारित पहचान है।

बहरहाल, इसमें कोई दो राय नहीं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय विदेश नीति को पारंपरिक निष्क्रियता से निकाल कर सक्रिय, निर्णायक और बहुआयामी कूटनीति का रूप दिया है। उनकी रणनीति केवल राजनयिक संवादों तक सीमित नहीं रही, बल्कि उन्होंने भारत को एक निर्णायक और आत्मविश्वासी राष्ट्र के रूप में स्थापित किया है।

आरक्षण पर विवाद से बचने की रणनीति, 6 सदस्यीय आयोग का होगा गठन

आर्यावर्त संवाददाता

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में आरक्षण की प्रक्रिया को पारदर्शी और विवाद मुक्त बनाने के लिए पंचायती राज विभाग ने महत्वपूर्ण कदम उठाया है। विभाग ने राज्य स्थानीय ग्रामीण निकाय समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन के लिए छह सदस्यीय आयोग का प्रस्ताव शासन को भेजा है। इस प्रस्ताव पर अंतिम मुहर कैबिनेट की बैठक में लगेगी। आयोग की जनसंख्या संबंधी रिपोर्ट के आधार पर ही ग्राम, क्षेत्र और जिला पंचायत चुनावों में आरक्षण की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी।

पंचायती राज विभाग ने आयोग के गठन के लिए प्रस्ताव भेजकर चुनावी तैयारियों को गति दे दी है। कैबिनेट की मंजूरी के बाद आयोग का गठन होगा और जनसंख्या डेटा संकलन का कार्य शुरू होगा। यह

प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान संभव हो सकेगा

जनसंख्या के आधार पर आरक्षण

2011 की जनगणना के अनुसार, उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जनजातियों (एसटी) की जनसंख्या 0.15677 प्रतिशत और अनुसूचित जातियों (एससी) की जनसंख्या 20.16982 प्रतिशत है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में इन वर्गों के लिए इसी अनुपात में सीटें आरक्षित की जाएंगी। वहीं, अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लिए आरक्षण की व्यवस्था में विशेष सावधानी बरती जा रही है। किसी ब्लॉक में ओबीसी की जनसंख्या 27 प्रतिशत से अधिक होने पर भी ग्राम प्रधान के पदों का आरक्षण 27 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा। हालांकि, यदि किसी ब्लॉक में ओबीसी की जनसंख्या 27 प्रतिशत से कम है, तो उसी अनुपात में आरक्षण लागू होगा। प्रदेश स्तर पर त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में ओबीसी के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण सुनिश्चित करना अनिवार्य होगा।

विवाद से बचने की रणनीति

पिछले नगर निकाय चुनावों में ओबीसी जनसंख्या के प्रतिशत को लेकर हुए विवादों से सबक लेते हुए सरकार इस बार सतर्क है। नगर निकाय चुनावों में विवाद के बाद सरकार ने समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कर जनसंख्या की सटीक जानकारी के आधार पर आरक्षण तय किया था। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में भी यही प्रक्रिया अपनाई जा रही है ताकि किसी तरह का विवाद न हो।

आयोग की भूमिका

प्रस्तावित राज्य स्थानीय ग्रामीण निकाय समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग विभिन्न जिलों का दौरा कर ओबीसी की जनसंख्या के बारे में विस्तृत जानकारी एकत्र करेगा। इसके बाद आयोग अपनी समग्र रिपोर्ट सरकार को सौंपेगा। उच्चपदस्थ सूत्रों के अनुसार, इस रिपोर्ट के आधार पर ही आरक्षण की प्रक्रिया शुरू होगी।

पंचायतीराज विभाग के इस कदम से न केवल आरक्षण की प्रक्रिया को निष्पक्ष और व्यवस्थित बनाने में मदद मिलेगी, बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में लोकतांत्रिक भागीदारी को भी बढ़ावा मिलेगा। सरकार का लक्ष्य है कि सभी वर्गों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में उचित प्रतिनिधित्व मिले और पंचायत चुनाव सुचारू रूप से संपन्न हों। आयोग के गठन और उसकी रिपोर्ट के बाद पंचायत चुनाव की प्रक्रिया में और तेजी आएगी। इस बीच, पंचायतीराज विभाग ने सभी संबंधित अधिकारियों को तैयारियों को अंतिम रूप देने के निर्देश दिए हैं।

32 लाख रुपए की लागत से मुक्तिधाम का निर्माण कार्य प्रगति पर

आर्यावर्त संवाददाता

सिंगाही-खीरी। कस्बे में सरकार की अंत्येष्टि स्थल निर्माण योजना के अंतर्गत नगर पंचायत की ओर से भेड़ौरा में मुक्तिधाम का निर्माण कार्य चल रहा है। इसके बन जाने से बारिश के सीजन में चार वार्ड के लिए अंत्येष्टि के लिए सुविधा रहेगी।

नगर पंचायत के हिंदुओं की अंत्येष्टि लेकर दो स्थल है। बाजार सहित करीब आठ वार्डो का अंतिम संस्कार ग्राम पंचायत सिंगाही देहात स्थित निघासन रोड के मुक्तिधाम पर होता है। इस मुक्तिधाम पर दो टीन शेड और बैठने की व्यवस्था है। इसके अलावा मोहल्ला भेड़ौरा और छावनी के अंतिम संस्कार ग्राम भेड़ौरा में जौराहा नदी के किनारे होते हैं। यहां पर किसी अंत्येष्टि के लिए टीन शेड और बैठने की व्यवस्था नहीं है। ग्राम पंचायत भेड़ौरा में इसको लेकर काफी समय से मांग की जा रही थी। इस पर नगर पंचायत चेयरमैन ने पैरवी करते हुए सरकार की ओर अंत्येष्टि स्थल निर्माण योजना के अंतर्गत सरकार की ओर 28 लाख की धनराशि स्वीकृत कराई। ग्राम पंचायत की एनओसी के बाद नगर पंचायत का फंड मिलाकर करीब 32 लाख की लागत से भेड़ौरा के मोहल्ले से लगी मुक्तिधाम की आवंटित जमीन पर निर्माण कार्य शुरू दिया है। नगर पंचायत चेयरमैन ने बताया कि अंत्येष्टि स्थल में अंत्येष्टि के लिए एक छायादार चबूतरा, परिजनों के लिए एक बरामदा, नहाने के लिए एक बोरिंग और सड़क का निर्माण होना है। इसके बाद बारिश के समय अंतिम संस्कार और उसमें शामिल होने वालों लोगों को काफी सहूलियत रहेगी।

अकाउंट नम्रता का, पैसा निकाल रही थी शीला... आधार के जरिए महिला ठग ने कैसे खाता किया खाली?

आर्यावर्त संवाददाता

अंबेडकर नगर। पैसा रखने के लिए अब तक सबसे सुरक्षित माना जाने वाला बैंक खाता भी सुरक्षित नहीं रह गया है। जालसाज कब आपकी मेहनत की कमाई पर हाथ साफ कर दें, इसकी आपको भनक भी नहीं लगेगी। उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर में पुलिस ने ऐसी ही एक जालसाजी का सनसनीखेज खुलासा किया है। साथ ही पुलिस ने एक महिला को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। मामला टांडा कोतवाली क्षेत्र का है। यहां नम्रता दूबे पत्नी शिशिर कुमार निवासी गांव फूलपुर जमुनीपुर का बैंक ऑफ बड़ौदा के मालीपुर शाखा में खाता है। बीते तीस अक्टूबर को नम्रता ने बैंक में शिकायत कर कहा कि उनके खाते से अज्ञात व्यक्ति द्वारा हेरा-फेरी कर अवैध रूप से पैसे निकाले गए। इसके बाद खाता धारक की शिकायत पर बैंक ने एक आंतरिक जांच कराई। जांच में पता चला कि शीला देवी नामक महिला द्वारा

तकरीबन 9 लाख 30 हजार रूपये निकाले गए हैं। बैंक के नियमों के अनुसार, खाता खोलने या पुराने खातों को संचालित करने के लिए खाते में आधार नंबर की फीडिंग आवश्यक है। खाताधारकों की सुविधा के लिए आधार नंबर से पैसे निकालने की व्यवस्था है। बैंक की इसी सुविधा का लाभ जालसाजों ने उठाया। वहीं पुलिस की जांच के मुताबिक, शीला देवी पत्नी मुन्ना निवासी शाहपुर कुरमौल कोतवाली टांडा की निवासी हैं। शीला देवी ने ग्राहक सेवा केंद्र मुबारकपुर के संचालक आशीष कुमार यादव के माध्यम से नम्रता दूबे के खाते में अपना आधार फीड करा दिया। आधार कार्ड की इस हेरा फेरी से शीला की पहुंच नम्रता के खाते तक हो गई।

आरोपी महिला ने ऐसे की जालसाजी

इसके बाद शीला ने आधार नंबर का इस्तेमाल कर अपना अंगूठा लगाकर नम्रता के खाते से पैसे निकालने शुरू कर दिए। शीला देवी और बीसी संचालक आशीष यादव ने मिलकर 9 लाख 30 हजार रूपये नम्रता के खाते से निकाल लिए। इन जालसाजों ने न सिर्फ नगद पैसा निकाला, बल्कि एक लाख रुपए की एफडी भी बनवा ली। इस पूरे मामले में टांडा कोतवाली प्रभारी दीपक सिंह रघुवंशी ने बताया कि जालसाजी कर पैसा निकालने वाली महिला को गिरफ्तार कर लिया गया है। मामले की जांच जारी है।

जोगराजपुर मनहरिया में खुलेआम यूरिया की ओवररेटिंग, प्रशासन बेखबर

पूरनपुर, पीलीभीत। यूरिया की कमी दिखाकर क्षेत्र में इसकी बड़े पैमाने पर ओवररेटिंग शुरू की जा रही है। दुकानदार मनमाने दामों पर इसे बेच रहे हैं। जिससे वे किसान परेशान हैं। जिनके खेत में पौध तैयार हो चुकी है और उन्हें अब इसकी जरूरत है। किसानों ने मनमानी पर अंकुश लगाने की मांग की है।समितियों पर पर्याप्त मात्रा में खाद न मिलने का फायदा दुकानदार उठा रहे हैं। मनमाने दामों पर यूरिया बेच रहे हैं।डीजल पेट्रोल के दामों में बढ़ोतरी से परेशान किसानों ने जैसे तैसे सिचाई कर बुई तो कर ली, लेकिन खाद का संकट उन्हें भारी पड़ रहा है। इससे पहले डीएपी और अब यूरिया की किल्लत उन्हें परेशान कर रही है। जिले के सेहरामऊ उत्तरी क्षेत्र के जोगराजपुर मनहरिया गांव में यूरिया खाद की खुलेआम ओवररेटिंग और कालाबाजारी से किसान बेहाल हैं। किसानों का आरोप है कि क्षेत्र के कुछ दुकानदार तय सरकारी दर पर यूरिया देने के बजाय मनमाना दाम वसूल रहे हैं।

होटल के बंद कमरे में कर रही थी रोमांस, तभी बच्चों के साथ आ धमका पति... देखते ही दीवार फांदकर भागी बीवी

मेरठ। इन दिनों सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ है। ये वीडियो एक धोखेबाज बीवी का है। जो पति और बच्चों को घर पर छोड़ बॉयफ्रेंड का बर्थडे मनाने एक होटल में पहुंची थी। पति को इसकी भनक लग गई। वो बच्चों के साथ उसी होटल पर जा पहुंचा। कमरा खुला तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। पत्नी अपने बॉयफ्रेंड संग रोमांस कर रही थी। पति को देख पत्नी की भी हालत खराब हो गई। उसने आव देखा न ताव। कपड़े उठाकर वहां से भागने लगी।

तभी पति ने उसका वीडियो बनाना शुरू कर दिया। पत्नी ने पहले होटल की बालकनी से एक घर की छत पर छलांग लगाई। फिर वहां पतली सी दीवार पर चलते हुए गली में कूद गई। वीडियो का संज्ञान लेते हुए पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि कोई तहरीर नहीं मिली है, लेकिन मामले में वीडियो के आधार पर जांच की जा रही है।

मगर बताया जा रहा है कि घटना उत्तर प्रदेश के मेरठ की है। बताया जा रहा है कि महिला अपने पति और बच्चों को छोड़कर बॉयफ्रेंड के साथ होटल में पार्टी करने आई थी। बॉयफ्रेंड का बर्थडे था इसलिए वो यहां आई थी। इस दौरान पति ने बच्चों को साथ लेकर होटल पर छापा मार दिया। होटल का कमरा खोलकर अंदर पहुंचे तो महिला अपने कपड़े समेटकर पीछे वाले गेट से होकर दूसरे मकान की छत पर कूद गई।

जान की परवाह किए बिना भागती रही

वहां से महिला होटल के पीछे पतली सी दीवार पर चलते हुए आगे बढ़ गई और नीचे गली में कूद गई। महिला बार-बार वीडियो बंद करने के लिए कहती रही। वीडियो में महिला आधे-कपड़ों में दिखाई दे रही है। महिला के हाथ में अपने कपड़े हैं और छत से कूदते हुए महिला बिना जान की परवाह किए छोटी से बाउंड्री पर होते हुए भाग रही है। वहीं, सोशल मीडिया पर लोग इस पर कई तरह की प्रतिक्रियाएं भी दे रहे हैं। एक यूजर ने लिखा- अच्छा हुआ प्रूफ हाथ लग गया। नहीं तो ये उल्टा केस कर देती। दूसरे ने लिखा- भाई आराम से, कहीं बदला ना ले ले वो तुमसे इसका। तीसरे ने लिखा- वाह, पुलिस से भी तेज।

कांवड़ यात्रा के दौरान करने वाले थे बवाल, हिस्ट्रीशीटर आबिद समेत 5 बदमाशों पर गैंगस्टर एक्ट

आर्यावर्त संवाददाता

बरेली। यूपी के बरेली जिले की सीबीगंज थाना पुलिस ने इलाके के कुख्यात हिस्ट्रीशीटर आबिद अली और उसके गिरोह पर सख्त कार्रवाई करते हुए गैंगस्टर एक्ट के तहत केस दर्ज कर लिया है। आबिद अली के अलावा उसके बेटे, भाई और साथी समेत कुल पांच लोगों को इस मामले में नामजद किया गया है। पुलिस को शक था कि यह गिरोह कांवड़ यात्रा के दौरान इलाके में बवाल कराने की फिराक में था। दरअसल, सीबीगंज के गांव अटरिया का रहने वाला आबिद अली कोई आम बदमाश नहीं है। इसके खिलाफ लूट, डकैती, हत्या, हत्या की कोशिश, रंगदारी और दबंगई जैसी करीब 34 संगीन धाराओं में अलग-अलग थानों में मुकदमे दर्ज हैं। इस वक्त आबिद हत्या की कोशिश के केस में पहले से ही जिला जेल में बंद है, लेकिन हैरानी की बात

यह है कि जेल में रहते हुए भी वह अपना गैंग चला रहा था।

सीबीगंज थाने के इंस्पेक्टर ने क्या बताया?

सीबीगंज थाने के इंस्पेक्टर अभिषेक सिंह ने बताया कि आबिद जेल से ही अपने गैंग के जरिए इलाके में दहशत फैलवा रहा था। आबिद के गैंग में उसका बेटा सोहिल अली, भाई वाजिद अली, दूसरा भाई नासिर अली और गुर्गा अमीर शाह शामिल है। पुलिस की जांच में सामने आया कि आबिद का गिरोह सावन के महीने में कांवड़ यात्रा के वक्त बवाल कराने की तैयारी में था। मकसद था इलाके में डर पैदा कर लोगों से जबरन पैसे वसूलना।

इन लोगों को भेजा गया जेल

इंस्पेक्टर ने बताया कि गिरोह के लोग पहले भी कई बार इलाके में दहशत फैला चुके हैं। इसी को देखते हुए सीबीगंज पुलिस ने आबिद और उसके गैंग के खिलाफ पूरा गैंग चार्ट तैयार कर डीएम को भेजा था। डीएम से मंजूरी मिलने के बाद गैंगस्टर एक्ट में रिपोर्ट दर्ज की गई। पुलिस ने कार्रवाई तेज करते हुए आबिद के भाई वाजिद अली और उसके साथी अमीर शाह को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। हालांकि आबिद का बेटा सोहिल अली और भाई नासिर अली अभी भी फरार हैं। पुलिस की टीमें उनकी तलाश में लगातार दबिश दे रही हैं। सीबीगंज पुलिस का कहना है कि जल्द ही बाकी दोनों को भी पकड़ लिया जाएगा। साथ ही गैंग के नेटवर्क को पूरी तरह ध्वस्त करने के लिए आगे भी सख्त कदम उठाए जाएंगे।

तहसीलदार के निर्णय से आहत किसान ने खायी कीटनाषक दवा, गम्भीर

सिरौलीगौसपुर बाराबंकी। भूमि संबंधित वाद में तहसीलदार के निर्णय से आहत किसान ने खरपतवार नाशक दवा पीकर आत्महत्या करने का प्रयास किया। इसकी जानकारी जब परिजनों को हुई तो वह उसे एक निजी अस्पताल में ले जाकर उपचार कराकर घर ले आये किंतु उसकी स्थिति में सुधार न होता देख पुनः किसी अस्पताल में ले जाकर भर्ती करवाया है। किसान की हालत गंभीर बनी हुई है। वही इस घटना के बाद से तहसील प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। थाना सफदरगंज क्षेत्र के ग्राम परसा निवासी लल्लाराम शोभाराम व लायकराम पुत्रगण आसाराम बनाम गूना उर्फ शीतलदेइ पत्नी बालगोविंद निवासी ग्राम गुलवरिया थाना करनैलगंज जनपद गोंडा का भूमि संबंधित वाद तहसीलदार न्यायालय सिरौलीगौसपुर में चल रहा था जिसमें पूर्व में हुए एक आदेश के विरुद्ध वादी लालाराम पक्ष द्वारा की गई।

नौकरी के नाम पर राजस्थान ले जाकर युवतियों को बेच रहा था गिरोह, गिरफ्तार

आर्यावर्त संवाददाता

गोरखपुर। नौकरी के नाम पर युवतियों को राजस्थान ले जाकर बेचने वाले गिरोह के चार सदस्यों को पिपराइच पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इसमें खरोबार में किराए के कमरे में रहने वाले आगरा के दंपत्ति युवतियों को फंसाते थे। फिर सभी आरोपित राजस्थान लेकर पहुंचते थे, जहां बागचंद प्रजापति उन्हें अपने घर रखता।

इसके बाद जिन युवकों की शादी नहीं हुई रहती थी उनसे रुपये लेकर युवतियों को बेच देते थे। पिपराइच क्षेत्र की रहने वाली एक युवती के गायब होने के बाद उसकी मां ने थाने में केस दर्ज कराया था।

जांच करने के बाद पुलिस ने युवती को उनवला रेलवे स्टेशन से बरामद करते हुए चारों को गिरफ्तार कर घटना का पर्दाफाश किया। चारों आरोपितों की पहचान राजस्थान के अजमेर गांधीनगर थाना के सुंदर नगर वार्ड नंबर 15 किशनगढ़ निवासी बागचंद प्रजापति, बानसीदरी थाना के हरमाड़ा निवासी सरवन पुरी, आगरा के ताजगंज थाना के शमशाबाद लोधी मार्ग निवासी सनी सिंह और उसकी पत्नी राधा सिंह के रूप में हुई।

इसमें सनी और उसकी पत्नी राधा खोराबार में किराए के कमरे पर रहते थे। राधा फरार चल रही सहजनवां की महिला के साथ मिलकर गरीब घर की युवतियों को नौकरी दिलाने के नाम पर फंसाती थी। जैसे ही युवती और उसके घर वाले तैयार होते थे, फिर गिरोह के अन्य सदस्य सक्रिय हो जाते थे।

जिसमें राधा का पति सनी सिंह और फरार चल रहा महराजगंज के निचलौल का युवक, युवतियों को लेकर दिल्ली पहुंचते थे। जहां फरार चल रहे एक युवक को लेकर राजस्थान के बागचंद प्रजापति के घर ले जाकर छोड़ आते थे। इसके बाद बागपत उन युवतियों को अपने स्थानीय गिरोह से संपर्क कर युवकों की शादी कराने के लिए बेच देते थे।

पिपराइच से गायब युवती को भी आरोपितों ने राजस्थान के सरवनपुरी के भाई को बेच दिया था। लेकिन, उसकी उम्र ज्यादा होने से युवती ने शादी से इंकार कर दिया और किसी तरह से वहां भाग निकली। जिसके बरामद होने के बाद पुलिस ने उसका बयान दर्ज किया और आरोपितों तक पहुंची और उन्हें गिरफ्तार किया।

राधा को भी ले गए थे बेचने

पुलिस की पूछताछ में सामने आया कि गिरोह के सदस्यों ने राधा को भी बहला-फुलसालकर बेचने के लिए लेकर राजस्थान गए थे। लेकिन, इस गिरोह का सदस्य सनी सिंह को वह पसंद आ गई और फिर दोनों ने शादी कर ली।

छांगुर बाबा की 'स्पेशल 50 टास्क फोर्स' की कहानी, अवैध धर्मांतरण का कोड हुआ डिकोड

आर्यावर्त संवाददाता

बलरामपुर। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले में अवैध धर्मांतरण रैकेट के सरगना जमालुद्दीन उर्फ की कहानी किसी माफिया डॉन की सक्रिप्ट से कम नहीं है। एक समय सड़कों पर अंगूठी और नग बेचने वाला यह शख्स न केवल 100 करोड़ की संपत्ति का मालिक बन गया, बल्कि उसने अपने काले साम्राज्य को संचालित करने के लिए 50 युवकों की एक विशेष टास्क फोर्स भी तैयार की थी। यह 'स्पेशल 50 टास्क फोर्स' छांगुर बाबा के इशारों पर काम करती थी। यूपी एटीएस अब इसकी जांच में जुटी है।

बलरामपुर के मधपुर गांव में छांगुर बाबा की आलीशान कोठी किसी किले से कम नहीं थी। तीन बीघे में फैली इस कोठी में 40 से 70 कमरे, सीसीटीवी निगरानी, प्राइवेट पावर प्लांट, सोलर पैनल, और विदेशी

नस्ल के घोड़ों, कुत्तों और जर्सी गायों के लिए मार्बल से सजा 'वीआईपी' अस्तबल तक मौजूद था। यही वह जगह थी, जहां छांगुर बाबा अपनी 'स्पेशल 50 टास्क फोर्स' को रखता था। इन युवकों के लिए कोठी में अलग-अलग कमरे, खाना-पीना, कपड़े और हर जरूरत की चीजें बाबा द्वारा मुहैया कराई जाती थीं।

यह कोठी छांगुर बाबा के काले साम्राज्य का मुख्य अड्डा थी, जहां वह धर्मांतरण का नेटवर्क संचालित करता था। जांच में पता चला कि कोठी का एक हिस्सा सरकारी जमीन पर अवैध रूप से बनाया गया था, जिसे प्रशासन ने 8-9 बुलडोजरों की मदद से तीन दिन तक चले अभियान में जमींदोज कर दिया।

'स्पेशल 50 टास्क फोर्स'

बाबा के 'आध्यात्मिक सैनिक'छांगुर बाबा ने करीब 50 युवकों की एक विशेष फोर्स तैयार की थी, जो उसके हर हुक्म को बिना सवाल उठाए मानती थी। ये युवक बाबा के इशारे पर धर्मांतरण की गतिविधियों में शामिल थे। सूत्रों के मुताबिक, इन युवकों को कोठी में ही ब्रेनवॉश किया जाता था। उन्हें बाकायदा ट्रेनिंग दी जाती थी, जिसमें बाबा का हर आदेश अंतिम फरमान माना जाता था, चाहे वह कानूनी हो या गैरकानूनी। बाबा खुद को धर्मगुरु और सूफी संत के रूप में पेश करता था, और इन युवकों को अपने 'आध्यात्मिक सेवक' बताकर अपने पास रखता था। जांच एजेंसियों के मुताबिक, इन युवकों का उपयोग न केवल धर्मांतरण के लिए किया जाता था, बल्कि स्थानीय स्तर पर भय और दबाव बनाने के लिए भी किया जाता था। कुछ मामलों में, इनका इस्तेमाल हिंसा फैलाने और लोगों को धमकाने में भी हुआ। सूत्रों का दावा है कि इनमें से कुछ युवक अन्य राज्यों से लाए गए थे, जिन्हें कोठी में रखकर मानसिक और वैचारिक रूप से तैयार किया जाता था। धर्मांतरण का 'रेट कार्ड' और प्रेमजाल छांगुर बाबा का नेटवर्क संगठित और खतरनाक था। जांच में खुलासा हुआ कि उसने धर्मांतरण के लिए जाति के आधार पर 'रेट लिस्ट' तैयार की थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय या सिख लड़कियों के लिए 15-16 लाख रुपये, पिछड़ी जातियों के लिए 10-12 लाख रुपये, और अन्य जातियों के लिए 8-10 लाख रुपये। गरीब और असहाय लोगों को धन, नौकरी या शादी का लालच देकर या धमकियों के जरिए धर्मांतरण के लिए मजबूर किया जाता था। बाबा का नेटवर्क राजस्थान, लखनऊ, बलरामपुर और पुणे तक फैला था, और उसने हज़ारो लोगों का धर्म परिवर्तन कराया था।

विदेशी फंडिंग और अंतरराष्ट्रीय साजिश की आशंका

एटीएस की जांच में चौंकाने वाला खुलासा हुआ कि छांगुर बाबा और उसके सहयोगियों ने 40 से अधिक बैंक खातों में 100 करोड़ रुपये से अधिक का लेन-देन किया, जिसमें खाड़ी देशों से विदेशी फंडिंग शामिल थी। बाबा ने 40-50 बार इस्लामिक देशों की यात्राएं की थीं, जिससे उसके अंतरराष्ट्रीय कनेक्शन की पुष्टि होती है। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) अब मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फंडिंग के पहलुओं की जांच कर रहा है, जबकि एनआईए भी टेरर फंडिंग के मामले में पूछताछ की तैयारी में है।

अवैध धर्मांतरण का CODE हुआ DECODE

छांगुर अपने साथियों से बातचीत में कोडवर्ड का प्रयोग करता था। जैसे-लड़कियां थीं 'प्रोजेक्ट' और 'मिट्टी पलटना' था मतांतरण।काजल करने का अर्थ था मानसिक रूप से प्रभावित करना था।दर्शन का मतलब बाबा से मिलवाना था।निकाह और शादी का वादा करने के बाद मतांतरण को नया जीवन शुरू करने की शर्त बताई जाती थी। कुछ युवाओं को कथित तौर पर इस्लामी शिक्षण संस्थानों में मुफ्त पढ़ाई और विदेश में काम का प्रलोभन भी दिया गया।

भारी बारिश का प्रकोप, पटरी धंसने से कालिंदी एक्सप्रेस को रोका, चालक ने दिखाई सूझबूझ

आर्यावर्त संवाददाता

कानपुर। शुक्रवार रात भारी वर्षा के चलते चौबेपुर के मरियानी गांव के पास रेलवे ट्रैक धंस गया। अंडरपास के पास यह घटना हुई। शनिवार की सुबह कालिंदी एक्सप्रेस के चालक ने इमरजेंसी ब्रेक लगाकर ठीक पहले गाड़ी रोक दी। रेलवे की सेक्टर टीम मौके पर पहुंची, जिसके बाद ट्रेन को बेहद धीमी गति से गुजारा गया।

बारादेवी में दो मकान ढहे, नौबस्ता में करंट से युवक की मौत

रात भारी वर्षा के चलते शहर के हालात बेहद खराब हो गए। बारादेवी में दो जर्जर मकान ढह गए। दोनों घरों में वर्षा का पानी भर गया था। हादसे में एक वृद्धा घायल हो गईं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दूसरी ओर नौबस्ता के ताज नगर में बिजली के पल में करंट उतरने से एक युवक की मृत्यु हो गई है। मृतक का नाम केशव तिवारी है जो कि 22/60 संजय गांधी नगर का रहने वाला है। इसके अलावा शहर के तमाम इलाकों में जलभराव है। डेढ़ दर्जन से ज्यादा स्थानों पर पेड़ गिरे हैं।

भोजन में नींबू निचोड़कर खाने से क्या होता है? जान लें इसके पीछे का विज्ञान

अक्सर कुछ लोग सब्जी या दाल में नींबू निचोड़कर खाना पसंद करते हैं। ऐसे में उनके मन में कई बार ये सवाल आता है कि क्या ऐसे खाना फायदेमंद होता है। बता दें कि भोजन में नींबू निचोड़कर खाना सेहत के लिए बहुत फायदेमंद है, जिसके बारे में आपको भी जानना चाहिए।

नींबू हमारी भारतीय रसोई का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। नींबू की खास बात यह है कि यह सबसे अधिक खट्टे फलों में से एक है। हम सभी जानते हैं कि नींबू को कई तरीके से अपनी डाइट में शामिल किया जा सकता है, इन्हीं में से एक प्रमुख तरीका है रोज सुबह नींबू पानी का सेवन करना। लेकिन बहुत से लोग अपने भोजन में भी नींबू निचोड़कर खाना पसंद करते हैं। अब बहुत से लोगों के मन में सवाल होता है कि भोजन में नींबू निचोड़कर खाना फायदेमंद होता है भी है या नहीं? आइए इस लेख में इसी के बारे में जानते हैं।

भोजन में नींबू निचोड़कर खाना बहुत फायदेमंद होता है, इसके कई

स्वास्थ्य लाभ होते हैं।

खासकर मानसून के मौसम में, जब पाचन अक्सर कमजोर पड़ जाता है और संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है, नींबू का सेवन किसी औषधि से कम नहीं। यह न सिर्फ पाचन को बेहतर बनाता है, बल्कि इम्यूनिटी को मजबूत कर पोषक तत्वों के अवशोषण में भी सहायता करता है। अब आइए भोजन में नींबू निचोड़कर खाने के फायदे जानते हैं।

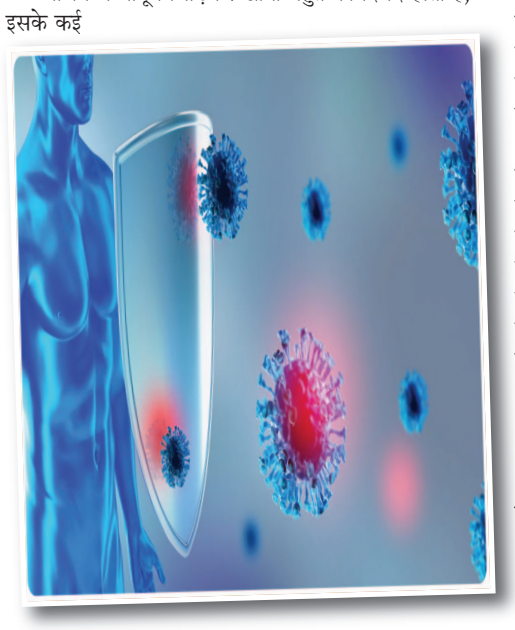

पाचन क्रिया में सुधार

नींबू में साइट्रिक एसिड होता है, जो पाचन तंत्र को उत्तेजित करता है और लार व पाचन रसों के उत्पादन को बढ़ाता है। दाल या सब्जी में नींबू निचोड़ने से पाचन एंजाइम्स सक्रिय होते हैं, जिससे भारी भोजन जैसे दाल, चावल या अन्य भारी भोजन का पचना भी आसान हो जाता है। यह कब्ज, अपच, और गैस की समस्या को कम करता है। नींबू का फाइबर युक्त रस आंतों की गतिशीलता को बढ़ाता है, जिससे मल त्याग नियमित होता है। रोजाना भोजन में थोड़ा नींबू निचोड़ने से पाचन तंत्र मजबूत होता है और मानसून में होने वाली पाचन समस्याएं कम होती हैं।

आयरन का अवशोषण बढ़ता है

नींबू में मौजूद विटामिन C आयरन के अवशोषण को बढ़ाता है। पालक, दाल, या चने जैसे खाद्य पदार्थों में नींबू निचोड़ने से शरीर में आयरन का अवशोषण कई गुना बढ़ सकता है। इससे एनीमिया जैसी गंभीर बीमारी की शिकायत नहीं होती है। विटामिन C आयरन को अधिक

घुलनशील बनाता है, जिससे यह आंतों में आसानी से अवशोषित हो जाता है।

इम्यूनिटी को मजबूती

नींबू विटामिन C और एंटीऑक्सिडेंट्स का भंडार है, जो इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है। यह शरीर को सर्दी, जुकाम, और वायरल इंफेक्शन से बचाने में मदद करता है। दाल या सब्जी में नींबू निचोड़ने से न केवल स्वाद बढ़ता है, बल्कि रोग प्रतिरोधक क्षमता भी मजबूत होती है।

सावधानियां

हालांकि नींबू के कई फायदे हैं, लेकिन इसका अधिक उपयोग नुकसानदायक हो सकता है। अत्यधिक नींबू निचोड़ने से दांतों का इनेमल कमजोर हो सकता है और पेट में जलन हो सकती है। बेहद गर्म भोजन में नींबू निचोड़ने से विटामिन C नष्ट हो सकता है। डायबिटीज या गैस्ट्रिक समस्या वाले लोग इसका सीमित उपयोग करें और डॉक्टर से सलाह लें।

ब्लो ड्राई करते वक्त कहीं आप भी तो नहीं कर रहे ये गलतियां, तो हो जाएं सावधान

बालों में ब्लो ड्राई करने से बाल काफी शाइनी और मैनेजेबल हो जाते हैं। लेकिन कुछ लोग ब्लो ड्राई करते वक्त कुछ आम गलतियां करते हैं, जिससे बालों को नुकसान पहुंचता है। तो चलिए आपको बताते हैं कौन सी है वो गलतियां जिनसे बचने की जररूत है।

अक्सर कुछ लोग बालों को सुखाने या उन्हें मैनेजेबल बनाने के लिए ब्लो ड्राई का इस्तेमाल करते हैं। बालों को ब्लो ड्राई करने से वो काफी स्ट्रेट और बाउंसी हो जाते हैं। लेकिन अगर ब्लो ड्राई करते समय कुछ बातों का ख्याल न रखा जाए तो इसका असर आपके बालों की हेल्थ पर पड़ सकता है। कई बार कुछ लोग बिना हीट प्रोकेटक्टर इस्तेमाल किए ही बालों में ब्लो ड्राई करने लगते हैं, जिससे बालों की जड़ें कमजोर हो सकती हैं।

वहीं, ऐसी ही कई और गलतियां हैं जो अक्सर लोग ब्लो ड्राई करते वक्त करते हैं। अगर आप भी इन्हीं गलतियों को दोहरा रहे हैं तो सावधान होने की जरूरत है। चलिए इस आर्टिकल में जानते हैं कि कौन सी हैं वो गलतियां जो बालों में ब्लो ड्राई करते वक्त नहीं करनी चाहिए और इनका बालों पर क्या नुकसान होता है।

अक्सर लोग गीले बालों में ही ब्लो ड्राई करने लगते हैं, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। गीले बालों में ब्लो ड्राई करने से बाल डैमेज हो सकते हैं। इसलिए हमेशा तब ही ब्लो ड्राई करनें जब बाल पूरी तरह से सूख जाएं। साथ ही बालों को कंघी से सुलझाते रहें इससे बाल कम टूटते हैं और बाल ज्यादा स्ट्रेट होते हैं।

बहुत ज्यादा ड्राई हेयर में ब्लो ड्राई करना

जैसे कुछ लोग बहुत ज्यादा गीले बालों में ब्लो ड्राई करते हैं। वैसे ही कुछ लोग बहुत ज्यादा ड्राई हेयर में ब्लो ड्राई कर लेते हैं। अगर आप ड्राई हेयर में ब्लो ड्राई करेंगे तो इससे उनके डैमेज होने का खतरा काफी ज्यादा बढ़ जाता है और बाल और ज्यादा रूखे-बेजान लग सकते हैं। इसलिए हमेशा थोड़े गीले बालों में ही ब्लो ड्राई करें।

स्कैल्प के पास ब्लो ड्राई करना

हमेशा कहा जाता है कि जब भी किसी हीटिंग टूल्स का इस्तेमाल बालों में करें तो इसे जड़ों से दूर रखना चाहिए। ब्लो ड्राई करते वक्त भी स्कैल्प को बचाना चाहिए। इससे बालों की जड़ें कमजोर हो जाती हैं , जिससे हेयर फॉल हो सकता है या बढ़ सकता है। साथ ही बाल ड्राई भी हो सकते हैं।

दिन में कई बार ब्लो ड्राई करना

अगर आप दिन में कई बार ब्लो ड्राई का इस्तेमाल कर रहे हैं तो सावधान हो जाइए। क्योंकि बालों में बार-बार हीटिंग टूल्स का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इससे बालों की जड़ें कमजोर हो जाती है। साथ ही बाल बहुत ज्यादा ड्राई भी हो सकते हैं। इसलिए बस दिन में 1 बार ही इसका इस्तेमाल करें।

86 करोड़ रुपये में निलाम हुआ हैंड बैग, आखिर इसमें क्या है ऐसा खास

मार्केट में आपने कई हजार के बैग देखे होंगे और सेलिब्रिटीज के पास लाखों की एसेसरीज भी होती है, लेकिन एक बैग ऐसा भी है जो लाखों में नहीं करोड़ो में बिका है और वो भी एक दो नहीं बल्कि पूरे 86 करोड़ है इस हैंड बैग की कीमत जान लें कि ये इतना खास क्यों है।

लड़कियों में हैंड बैग को लेकर भी काफी क्रेज रहता है। एक बेहतरीन बैग लुक में स्टाइल के साथ ही स्टेटस को भी दिखाता है। इसके लिए लोग हजारों से लेकर लाखों तक खर्च करते हैं, लेकिन एक हैंड बैग की कीमत इतनी है कि आप एक लग्जरी बंगला खरीद सकते हैं। ये बात सुनने में हैरान कर देने वाली है, लेकिन सच है। फ्रांसिसी ब्रांड हर्मिस (Hermes) द्वारा बनाए गए ऑरिजनल बिर्किन बैग को ऑक्शन में बेचा गया। बहुत पुराना होने के बावजूद इस बेहद रेयर बैग की नीलामी में कई रिकॉर्ड टूटे। शुरुआत में ही एक मिलियन का रिकॉर्ड बनने के दौरान इसकी कई बोलियां लगाई गईं। सिर्फ 10 मिनट के ऑक्शन में जापान के एक व्यक्ति (collector) ने इस ब्लैक हैंड बैग को 8 ।6 मिलियन यूरो यानी 10 मिलियन डॉलर में खरीद लिया। बता दें कि इसकी भारतीय कीमत करीब 86 करोड़ रुपये है।

इतनी महंगी कीमत में बिकने वाले इस बैग के बनाए जाने की कहानी भी बहुत खास है। ये बैग स्टेटस और एक्सक्लूसिविटी का सिंबल बन चुका है। बता दें कि ये बैग फैशन की दुनिया में बेहद खास जगह रखता है क्योंकि इसे ब्रिटिश सिंगर और एक्टर जेन बिर्किन द्वारा यूज किया गया था। लोग इसे इन्वेस्टमेंट पीस के तौर पर खरीदते हैं, क्योंकि टाइम के साथ इस बैग की वैल्यू बढ़ती चली जाती है। तो चलिए ये भी जान लेते हैं कि ऐसा क्यों है।

कैसे बना "ओरिजिनल बिर्किन" बैग?

हर्मिस ने ये बैग फर्स्ट बिर्किन बैग, ब्रिटिश एक्ट्रेस और सिंगर जेन बिर्किन के लिए डिजाइन किया गया था। जिसकी कहानी भी काफी दिलचस्प है। दरअसल बात 1984 की है जब हर्मिस के पूर्व अध्यक्ष जीन-लुई डुमास पेरिस से लंदन जाने वाली फ्लाइट में एक्ट्रेस बिर्किन के पास वाली सीट पर बैठे हुए थे, इस दौरान जेन बिर्किन (जो उस वक्त तीन बेबी की मां थीं), उन्होंने इस दौरान कहां कि उन्हें अपनी जरूरतों के मुताबिक एक ऐसा बैग नहीं मिल रहा है कि जिसमें वो सारा सामान आसानी से रख सकें। और इसी वजह से उन्होंने एक बड़ी बास्केट अपने साथ रखी थी जो फ्लाइट लेने के दौरान गलती से गिर गई। इसक बाद जेन बिर्किन ने कहां कि वह एक ऐसा बैग चाहती हैं जो उनके सूटकेस से आधे साइज का हो। हर्मिस ने एक साल बाद 1985 में यह बैग बनाकर दिया।

जेन बिर्किन ने इतने साल किया ये बैग यूज?

हर्मिस ने इस बैग के बाद जेन बिर्किन को 4 बैग गिफ्ट में दिए, लेकिन ये बैग काफी खास है, क्योंकि स्टाइल आइकन बिर्किन ने 1985 से 1994 तक लगभग हर दिन इसका इस्तेमाल किया और इसी वजह से यह लग्जरी स्टेटस का अल्टीमेट सिंबल बन गया। यह भी कहा जाता है कि बिर्किन इसे चैरिटी के लिए दान कर दिया करती थी। 1994 में सिंगर जेन बिर्किन ने इसे एड्स अनुसंधान के लिए बेच दिया और उसके बाद ये बैग कई लोगों के पास जा चुका है। हालांकि इसे न्यूऑर्क के म्यूजियम ऑफ मॉर्डन आर्ट और लंदन के विक्टोरिया एंड अल्बर्ट म्यूजियम के ऑक्शन्स (नीलामी) में इसे पब्लिकली दोबारा से शो किया गया।

कहां था लोग इस बैग को याद रखेंगे?

साल 2023 में 76 साल की उम्र में जेन बिर्किन ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया था और उन्होंने इससे कुछ समय पहले मजाक में कहा था कि लोग उन्हें इस आइकॉनिक स्टाइल इंस्पिरेशन के लिए सबसे ज्यादा याद रखेंगे और "जब मैं मर जाऊंगी तो लोग शायद सिर्फ़ उस बैग के बारे में ही बात करेंगे।" वाकई ये बैग आज एक सबसे ज्यादा पहचानी जाने वाली महंगी एक्सेसरीज बन गई है।

क्यों खास है ये बैग?

ऑरिजनल बिर्किन के बाद इसके कई बैग बने लेकिन इस हैंडबैग के आकापस इसमें लगे मेटल रिंग्स, हार्डवेयर जैसे शोल्डर स्ट्रेप और बाकी डिटेल को कभी कॉपी नहीं किया गया यानी ये एक सिंगल पीस है। सबसे खास बात है कि बैक के फ्लैप पर सिंगर के नाम के इनिशियल्स यानी नाम के अक्षरों "जे।बी।" लिखा हुआ है साथ ही शोल्डर के स्ट्रेप पर वन पेयर सिल्वर नेल क्लिपर लटके हुए हैं, दरअसल जेन बिर्किन को अपने नेल्स फाइन तरह से कटे हुए पसंदे थे और इस वजह से वह इस क्लिपर को अपने साथ यूज के लिए रखती थीं। ये बैग एक रॉयल्टी क्रिएट करता है, क्योंकि इस पुराने बैग पर बिर्किन की डेली लाइफस्टाइल के निशान मौजूद हैं। जिसमें मानवीय संगठनों "मेडिसिन डू मोंडे" और "यूनिसेफ" के दो स्टिकर के कारण रंग उड़ना भी शामिल है।`

आईटी मंत्रालय और बिट्स-पिलानी मिलकर सरकारी और सार्वजनिक क्षेत्र के पेशेवरों को साइबर सिक्योरिटी की देंगे ट्रेनिंग

नई दिल्ली, एजेंसी। भारत की साइबर सुरक्षा क्षमताओं को मजबूत करते हुए सीईआरटी-इन और बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस (बिट्स) पिलानी समूह ने सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र और उद्योग जगत के पेशेवरों के लिए साइबर सुरक्षा में व्यावसायिक विकास कार्यक्रम शुरू करने के लिए आपस में सहयोग किया है।

सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और उद्योग जगत के कार्यरत पेशेवरों के लिए साइबर सुरक्षा में एक 8-सप्ताह का कार्यक्रम तैयार किया गया है, जिसे बिट्स पिलानी अपने हैदराबाद कैंपस स्थित सेंटर फॉर रिसर्च एक्सीलेंस इन नेशनल सिक्योरिटी (सीआरईएनएस) के माध्यम से, अपने टेक्नोलॉजी साझेदार रैपिफज के साथ, सीईआरटी-इन के मार्गदर्शन में संचालित करेगा।

सीईआरटी-इन साइबर घटना प्रतिक्रिया के लिए भारत की राष्ट्रीय एजेंसी है। इस सहयोग का उद्देश्य साइबर सुरक्षा में स्ट्रक्चर्ड, उच्च-प्रभाव क्षमता निर्माण की बढ़ती मांग को पूरा करना है, जो उभरते डिजिटल खतरों और साइबर सुरक्षा चुनौतियों के बीच बढ़ते महत्व का क्षेत्र है।

सीईआरटी-इन के डायरेक्टर जनरल डॉ. संजय बहल ने कहा, भारत की साइबर मजबूत क्षमता न केवल स्वदेशी कटिंग-एज टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल और विकास में नजर आती है, बल्कि डिजिटल और क्वांटम युग की उभरती चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार एक जीवंत, उच्च कुशल प्रतिभा समूह के विकास में भी अपनी असली ताकत तलाशती है। उन्होंने बताया कि बिट्स-पिलानी के साथ सीईआरटी-इन का सहयोग इस यात्रा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

यह प्रयास पेशेवरों को कटिंग-एज साइबर सिक्योरिटी विशेषज्ञता से लैस करने के साथ-साथ उद्योग की उभरती मांगों और शैक्षणिक उत्कृष्टता के बीच एक गतिशील तालमेल को बढ़ावा देने के लिए डिजाइन किया गया है।

आईटी मंत्रालय के अनुसार, यह कार्यक्रम 19 जुलाई से शुरू होगा और सभी क्षेत्रों के पेशेवरों के लिए खुला है, जिनमें बिना किसी पूर्व कोडिंग अनुभव वाले लोग भी शामिल हैं।

कार्यक्रम सफलतापूर्वक पूरा होने पर प्रतिभागियों को साइबर सुरक्षा में एक व्यावसायिक विकास प्रमाणपत्र प्राप्त होगा, जिसे सीईआरटी-इन और बिट्स पिलानी द्वारा सह-ब्रांड किया जाएगा।

दुनिया भर में बढ़ते साइबर खतरों के दौर में, सीईआरटी-इन भारत के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की सुरक्षा में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 70बी के तहत साइबर घटनाओं से निपटने के लिए राष्ट्रीय एजेंसी के रूप में नामित, घटनाओं की रोकथाम और रियल टाइम थ्रेट मिटिगेशन से लेकर सिक्योरिटी क्वालिटी मैनेजमेंट सर्विसेज के माध्यम से साइबर मजबूती बढ़ाने तक, सीईआरटी-इन भारत की साइबर सुरक्षा रणनीति के मूल में है।

बिट्स पिलानी के ग्रुप वाइस चांसलर, प्रोफेसर वी. रामगोपाल राव ने कहा, बिट्स पिलानी में, हम साइबर सुरक्षा को न केवल एक तकनीकी चुनौती के रूप में देखते हैं, बल्कि एक राष्ट्रीय प्राथमिकता के रूप में भी देखते हैं।

आपके लिए कौन-सा प्लान है बेस्ट, यहां समझें अपने फायदे की बात

टर्म इंश्योरेंस प्लान और लाइफ इंश्योरेंस प्लान को लेकर ज्यादातर लोग दुविधा में रहते हैं कि कौन-सा प्लान लेना ज्यादा सही है। अगर आप भी इन दोनों प्लान में से अपने लिए एक बेहतर प्लान को नहीं चुन पा रहे हैं तो इन दोनों प्लान के बीच का अंतर समझना जरूरी है। दोनों प्लान के बीच अंतर रिटर्न को लेकर देखा जाता है।

टर्म इंश्योरेंस प्लान और लाइफ इंश्योरेंस प्लान को लेकर ज्यादातर लोग दुविधा में रहते हैं कि कौन-सा प्लान लेना ज्यादा सही है। अगर आप भी इन दोनों प्लान में से अपने लिए एक बेहतर प्लान को नहीं चुन पा रहे हैं तो इन दोनों प्लान के बीच का अंतर समझ सकते हैं-

टर्म इंश्योरेंस प्लान और लाइफ इंश्योरेंस प्लान के बीच अंतर समझने से पहले इन दोनों ही प्लान का मतलब जानना जरूरी है-

टर्म इंश्योरेंस प्लान क्या है

टर्म इंश्योरेंस प्लान लाइफ इंश्योरेंस प्लान है। इस प्लान में एक तय समय के लिए कवर मिलता है। प्लान की अवधि के दौरान प्लान लेने वाले शख्स के साथ कोई बड़ी अनहोनी घट जाए तो परिवार के सदस्यों में नॉमिनी को पैसे मिलते हैं।

यह एक तय और निश्चित राशि होती है। टर्म इंश्योरेंस प्लान में हर साल प्रीमियम भरा जाता है। टर्म इंश्योरेंस प्लान में मासिक, त्रैमासिक, छमाही या सालाना आधार पर प्रीमियम भरा जाता है। प्लान की अवधि खत्म होने के बाद इस प्लान में किसी तरह का कोई रिटर्न नहीं मिलता।

लाइफ इंश्योरेंस प्लान क्या है

टर्म इंश्योरेंस प्लान से अलग लाइफ इंश्योरेंस प्लान निवेश के लिए एक बढ़िया प्लान माना जाता है। इस प्लान में लाइफ कवर के साथ निवेश का फायदा मिलता है।

प्लान की अवधि के दौरान इंश्योरेंस लेने वाले व्यक्ति की मौत हो जाती है तो परिवार के सदस्यों में नॉमिनी को डेथ बेनेफिट, निवेश की गई रकम के साथ ब्याज दिया जाता है।

इंश्योरेंस की अवधि पूरी होने पर मैच्योरिटी के तौर पर निवेश की गई रकम के साथ ब्याज दिया जाता है।

लाइफ इंश्योरेंस VS टर्म इंश्योरेंस

दोनों ही प्लान में बीमित व्यक्ति को इंश्योरेंस की अवधि के दौरान दुर्घटना होने पर डेथ बेनेफिट मिलता है। हालांकि,टर्म इंश्योरेंस प्लान और लाइफ इंश्योरेंस प्लान के बीच अंतर रिटर्न को लेकर देखा जाता है।

लाइफ इंश्योरेंस प्लान में प्रीमियम पर रिटर्न मिलता है, वहीं टर्म इंश्योरेंस में प्रीमियम पर रिटर्न नहीं मिलता है।

मैच्योरिटी बेनेफिटः लाइफ इंश्योरेंस प्लान में मैच्योरिटी पूरी होने पर जमा की गई प्रीमियम राशि पर ब्याज के साथ एकमुश्त राशि मिलती है। वहीं, दूसरी ओर टर्म इंश्योरेंस में मैच्योरिटी बेनेफिट नहीं मिलता।

प्रीमियम राशिः टर्म इंश्योरेंस में लाइफ कवर मिलता है। यही वजह है कि इस प्लान में प्रीमियम की राशि कम होती है। वहीं, लाइफ इंश्योरेंस में प्रीमियम की राशि ज्यादा होती है।

लोन की सुविधाः टर्म इंश्योरेंस में किसी तरह के लोन की सुविधा नहीं मिलती है। वहीं, दूसरी ओर कई वर्षों तक प्रीमियम जमा करने पर लाइफ इंश्योरेंस प्लान के साथ लोन की सुविधा पाई जा सकती है।

कौन-सा प्लान है बेहतर

जानकारों की मानें तो दोनों ही प्लान के अलग-अलग फायदे हैं। ऐसे में यह व्यक्ति की जरूरत पर निर्भर करता है कि उसे कौन-सा प्लान चुनना चाहिए।

कम समय के लिए प्लान चाहिए तो टर्म इंश्योरेंस सस्ता पड़ेगा। वहीं, लाइफ टाइम के लिए कवरेज चाहिए तो महंगे प्रीमियम के साथ लाइफ इंश्योरेंस प्लान सही है।

दुनिया अमेरिका के टैरिफ से परेशान है, लेकिन इस तानाशाह को मिल गया फायदा!

वॉशिंगटन, एजेंसी। जब पूरी दुनिया अमेरिकी टैरिफ की मार से परेशान है, म्यांमार का सैन्य शासक मिन आंग ह्लाइंग इसे सम्मान बताकर खुशियां मना रहे हैं। ट्रंप की ओर से मिले एक औपचारिक लेटर को म्यांमार की तानाशाही सरकार ने ऐसे पेश किया जैसे उन्हें वैश्विक मान्यता मिल गई हो। दरअसल, अमेरिका ने म्यांमार के उत्पादों पर 40 फीसदी का नया टैरिफ लगाने का ऐलान किया है, जो 1 अगस्त से लागू होगा। ये वही म्यांमार है जिसे अमेरिका और यूरोप अब तक आधिकारिक सरकार नहीं मानते और जिस पर तमाम प्रतिबंध लगाए गए हैं। लेकिन जनरल ह्लाइंग को इस टैरिफ में नुकसान नहीं, एक अवसर नजर आ रहा है। जनरल ह्लाइंग वही नेता हैं जिन पर रोहिंग्या नरसंहार का आरोप है और जिन्होंने नोबेल विजेता आंग सान सू ची की लोकतांत्रिक सरकार को 2021 में तख्तापलट कर गिरा दिया। सू ची अब बंद दरवाजों के पीछे हुई सुनवाई के बाद 27 साल की सजा काट रही हैं।

चिट्ठी को बताया आमंत्रण, मिलने की जताई इच्छा

राज्य नियंत्रित अखबार Global New Light of Myanmar के मुताबिक, ट्रंप का ये पत्र न सिर्फ ईमानदारी से सराहा गया, बल्कि जनरल ने इसे अमेरिकी अर्थव्यवस्था में भागीदारी का संकेत बताया। उन्होंने अमेरिका को बातचीत के लिए एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भेजने की पेशकश भी कर डाली। ह्लाइंग ने यहां तक कहा कि अमेरिका को म्यांमार पर लगे आर्थिक प्रतिबंधों को हटाने पर विचार करना चाहिए क्योंकि ये दोनों देशों के साझा हितों और समृद्धि में बाधा डालते हैं।

ट्रंप की तारीफ, लोकतंत्र पर हमला

चिट्ठी की आड़ में जनरल ह्लाइंग ने ट्रंप की जमकर तारीफ भी की। उन्होंने ट्रंप को सच्चा राष्ट्रभक्त बताया और उनके वैश्विक शांति के प्रयासों की सराहना की। यही नहीं, उन्होंने ट्रंप की उस शिकायत को भी दोहराया जिसमें ट्रंप ने 2020 के अमेरिकी चुनाव में धांधली का आरोप लगाया था। ह्लाइंग ने कहा कि जैसे ट्रंप को चुनाव में गड़बड़ी का सामना करना पड़ा, म्यांमार में भी कुछ ऐसा ही हुआ। जबकि सच्चाई ये है कि म्यांमार में 2020 का चुनाव अंतरराष्ट्रीय स्तर पर निष्पक्ष और स्वतंत्र माना गया था। लेकिन सेना ने धोखाधड़ी का बहाना बनाकर सत्ता पर कब्जा कर लिया।

इजराइल से सीजफायर के बाद ईरान में अफगानियों पर पड़ी मार, बाहर निकाले गए 5 लाख लोग

तेल अवीव, एजेंसी। इजराइल और ईरान के बीच हालिया संघर्ष खत्म होने के कुछ ही दिन बाद ईरान में अफगान नागरिकों पर कार्रवाई तेज हो गई है। महज 16 दिनों में 5 लाख से ज्यादा अफगानों को ईरान से बाहर निकाल दिया गया है।संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के मुताबिक, ये दशक के सबसे बड़े जबरन विस्थापन में से एक माना जा रहा है।

CNN की एक रिपोर्ट के मुताबिक 24 जून से 9 जुलाई के बीच 5 लाख 8 हजार से ज्यादा अफगान नागरिकों ने ईरान-अफगानिस्तान बॉर्डर पार किया है। एक दिन में 51,000 लोगों को बाहर किया गया, जो अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। ईरान ने बीते रविवार तक का अल्टीमेटम दिया था कि बिना कागजों वाले सभी अफगान नागरिक देश छोड़ दें।

लंबे समय से थी तैयारी, अब मिला मौका?

ईरान लंबे समय से ये संकेत देता रहा है कि वो देश में रह रहे अवैध अफगान प्रवासियों को निकालना चाहता है। इन अफगानों में बड़ी संख्या उन लोगों की है जो बेहद कम वेतन में ईरान के शहरों में मजदूरी करते हैं। तेहरान, मशहद और इस्फहान जैसे शहरों में ये मजदूर निर्माण, सफाई और खेतों में काम करते हैं। लेकिन इजराइल के साथ 12 दिन की जंग खत्म होते ही अफगानों पर कार्रवाई अचानक तेज हो गई।

आरोप- अफगान कर रहे थे इजराइल के लिए जासूसी

ईरान की ओर से कहा जा रहा है कि कुछ अफगान नागरिक इजराइल के लिए जासूसी कर रहे थे, इसलिए सुरक्षा के लिहाज से ये जरूरी है। वहीं ईरानी मीडिया में ऐसा ही दावा किया जा रहा है। एक कथित वीडियो भी दिखाया गया जिसमें एक अफगान युवक 2000 डॉलर के बदले जर्मनी में बैठे किसी हैंडलर को लोकेशन की जानकारी देने की बात कबूल कर रहा है। हालांकि इस वीडियो की पुष्टि नहीं हुई है और आरोप भी सबूतों के बगैर ही हैं।

आलोचना के घेरे में ईरान

मानवाधिकार संगठनों का कहना है कि ईरान इन जासूसी के आरोपों को बहाना बनाकर लंबे समय से पलायन की योजना पर काम कर रहा था। अब उस पर अमल शुरू हो चुका है। आलोचकों का कहना है कि सरकार ने आंतरिक असंतोष को दबाने के लिए अफगानों को निशाना बनाया है, जो पहले से ही एक कमजोर और शोषित समुदाय है।

अफगानिस्तान में हालात गंभीर

ईरान से निकाले गए अफगानों के लिए हालात आसान नहीं हैं। तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर है और बॉर्डर पर बनाए गए अस्थायी कैंप्स में सुविधाएं सीमित हैं। इस साल अब तक ईरान और पाकिस्तान से करीब 16 लाख अफगान अपने देश लौट चुके हैं। UNHCR का अनुमान है कि साल के अंत तक यह संख्या 30 लाख तक पहुंच सकती है। जानकारों की मानें तो बिना जांच-पड़ताल और कानूनी प्रक्रिया के इतने बड़े पैमाने पर पलायन, भविष्य में और संकट खड़ा कर सकता है।

काबुल में तबाही का ट्रेलर! बन जाएगा बिना पानी वाला दुनिया का पहला शहर

काबुल। कभी अफगानिस्तान की रूह कहा जाने वाला काबुल, आज अपने अस्तित्व के सबसे बड़े संकट से जूझ रहा है। हिंदूकुश की पहाड़ियों के बीच बसे इस ऐतिहासिक शहर की पहचान सिर्फ अफगानिस्तान की राजधानी के तौर पर नहीं, बल्कि एक सांस्कृतिक और आर्थिक केंद्र के रूप में भी रही है। लेकिन अब यही काबुल दुनिया का पहला ऐसा बड़ा शहर बनने की कगार पर है, जहां 2030 तक पानी पूरी तरह खत्म हो सकता है। नॉनप्रॉफिट मर्सी कॉप्स की रिपोर्ट में इसकी चेतावनी दी गई है। एक ताजा रिपोर्ट के मुताबिक, बीते एक दशक में काबुल के भूजल स्तर में 25 से 30 मीटर तक गिरावट दर्ज की गई है। हर साल जितना पानी जमीन से निकाला जा रहा है, उससे 4.4 करोड़ क्यूबिक मीटर ज्यादा निकासी हो रही है। यानी जलस्तर की प्राकृतिक भरपाई से कहीं ज्यादा तेज़ी से पानी का दोहन हो रहा है।

जल संकट के पीछे कौन-कौन से कारण?

सालों तक चले संघर्ष ने काबुल में आधुनिक जल प्रणाली में निवेश को रोक दिया। नतीजा ये कि जमीन का पानी तेजी से खत्म हो रहा है और जो बचा है वो भी जहरीला हो चुका है। यूनिसेफ की रिपोर्ट के मुताबिक काबुल में आधे से ज्यादा बोरवेल सूख चुके हैं और करीब 80 फीसदी भूजल दूषित हो चुका है। अगर यही स्थिति रही तो 2030 तक यहां की जमीन के नीचे मौजूद जल स्रोत पूरी तरह खत्म हो जाएंगे। जलवायु परिवर्तन की मारः जल संकट की सबसे बड़ी वजह है बदलता मौसम चक्र। बीते कुछ वर्षों से अफगानिस्तान में बर्फबारी घट रही है, बर्फ समय से पहले पिघल रही है और सूखे की घटनाएं बार-बार हो रही हैं। 2023 में सामान्य से 40-50% कम बारिश हुई, जिससे भूजल को रिचार्ज होने का मौका नहीं मिला।

प्रशासनिक विफलताएंः जल प्रबंधन, पाइपलाइन मरम्मत, और वर्षाजल संग्रहण जैसे बुनियादी कामों की लगातार अनदेखी की गई। सरकार की नाकामी ने जल संकट को और गहरा बना दिया है। 170 मिलियन डॉलर की लागत वाला पंजशीर नदी से पानी लाने वाला प्रोजेक्ट वर्षों से सिर्फ कागजों में अटका पड़ा है।

तेजी से बढ़ती आबादीः 2001 में काबुल की आबादी जहां 10 लाख थी, वहीं अब यह 60 लाख के पार पहुंच चुकी है। युद्ध, आंतरिक विस्थापन और अस्थिर शासन व्यवस्था के चलते लाखों लोग काबुल में बस गए। नतीजा ये कि सीमित जल संसाधनों पर भारी बोझ पड़ गया।

किसने बढ़ाई मुसीबत?

काबुल में 500 से अधिक बोतलबंद पानी और सॉफ्ट ड्रिंक कंपनियां काम कर रही हैं, जो भूजल का अंधाधुंध दोहन कर रही हैं। सिर्फ अलोकोजे कंपनी ही हर साल 1 अरब लीटर पानी निकाल रही है। इसके अलावा, 400 हेक्टेयर में फैले ग्रीनहाउस सालाना करीब 4 अरब लीटर पानी की खपत कर रहे हैं।

अब अगर कुछ नहीं किया तो क्या होगा?

अगर अंतरराष्ट्रीय समुदाय और अफगान सरकार ने जल्द कोई ठोस कदम नहीं उठाया, तो हालात और बिगड़ेंगे। अनुमान है कि काबुल से लगभग 30 लाख लोग विस्थापित हो सकते हैं। ये संकट सिर्फ राजधानी तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि देश के अन्य हिस्सों में भी फैल सकता है। खासतौर पर उत्तरी, उत्तर-पश्चिमी और उत्तर-पूर्वी प्रांतों में सूखा तेज़ी से फैल रहा है। यहां फसलें बर्बाद हो रही हैं, और पशुधन मर रहे हैं। खाद्य और कृषि संगठन (FAO) के मुताबिक, खेती और पशुपालन पर निर्भर लाखों लोगों की रोज़ी-रोटी खतरे में है।

क्या है उम्मीद की किरण?

पंजशीर नदी से काबुल तक पानी लाने की योजना एक उम्मीद की किरण जरूर है। इसका डिज़ाइन 2024 के अंत तक तैयार हो चुका है और सरकार इसके लिए निवेशकों की तलाश में है। अगर इसे समय पर मंजूरी और फंडिंग मिल गई, तो करीब 20 लाख लोगों को साफ पानी मिल सकेगा।

टेक्सास में बाढ़ पीड़ितों से मिले ट्रंप, बोले- ऐसी तबाही पहले कभी नहीं देखी; FEMA पर साधी चुप्पी

यरुशलम, एजेंसी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को टेक्सास के केरविल शहर का दौरा किया, जहां 4 जुलाई को आई भीषण बाढ़ ने भारी तबाही मचाई थी। इस बाढ़ में अब तक कम से कम 120 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 170 से ज्यादा लोग लापता हैं। ट्रंप ने पीड़ित परिवारों से मुलाकात की और राहत कार्यों में जुटे स्थानीय अधिकारियों की सराहना की। इस दौरान उन्होंने पहली बार भावुक लहजे में कहा कि उन्होंने ऐसी तबाही पहले कभी नहीं देखी।

ट्रंप लंबे समय से फेडरल इमरजेंसी मैनेजमेंट एजेंसी (फेमा) को खत्म करने की बात करते रहे हैं। लेकिन टेक्सास में भारी नुकसान देखने के बाद उन्होंने फेमा की भूमिका पर कोई टिप्पणी नहीं की। इसके बजाय उन्होंने कहा कि हम जो भी कर सकते हैं, टेक्सास के लिए करेंगे। ट्रंप ने 8 और काउंटियों को 'डिजास्टर जोन' घोषित कर, उन्हें फेडरल मदद दिलाने का ऐलान भी किया।

बाढ़ पीड़ितों के लिए भावुक हुए ट्रंप

ट्रंप ने केरविल में आपातकालीन संचालन केंद्र का दौरा किया और कहा कि यहां जो लोग खोज और बचाव अभियान चला रहे हैं, वे अविश्वसनीय हैं। ऐसा काम शायद ही कोई कर पाए। उन्होंने 'कैंप मिस्टिक' का विशेष रूप से जिक्र किया, जहां 27 लड़कियों की मौत हुई। मेलानिया ट्रंप ने भी स्थानीय युवतियों से मुलाकात की, जिन्होंने उन्हें एक खास ब्रेसलेट भेंट किया, जो मृत बालिकाओं की याद में बनाया गया था।

राजनीतिक हमलों से बचते दिखे ट्रंप

पहले के विपरीत इस दौरे में ट्रंप ने राजनीतिक बयानबाजी से परहेज किया। उन्होंने कहा कि मैं राजनीति की बात नहीं करना चाहता। हम यहां पीड़ितों के लिए आए हैं। हालांकि उन्होंने एक बार फिर दावा किया कि उनकी नीतियों से देश में अंडों के दाम घटे हैं। इस दौरान उन्होंने फेमा को लेकर भी सकारात्मक बातें कहीं, जो कि कुछ हफ्ते पहले तक बंद करने की उनकी योजना का हिस्सा थी। उन्होंने टेक्सास के सांसद चिप रॉय की भी तारीफ की, जिन्होंने पहले ट्रंप के टैक्स बिल का विरोध किया था। ट्रंप ने कहा कि चिप आसान नहीं हैं, लेकिन अच्छा काम करते हैं।

चुनाव से पहले नीतीश सरकार का मास्टरस्ट्रोक, बिहार में अब 100 यूनिट मुफ्त बिजली देने की तैयारी

नई दिल्ली, एजेंसी। बिहार में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। चुनाव से पहले, नीतीश सरकार मतदाताओं को आकर्षित करने के लिए नई-नई योजनाओं का ऐलान कर रही है। पिछले दिनों पेंशन में बढ़ोतरी की गई थी। अब, बिहार सरकार ने मुफ़्त बिजली देने की तैयारी में है। यह फैसला सीधे तौर पर आम लोगों की जेब पर असर डालेगा, पैसों की बचत होगी। इसके साथ ही कहा जा रहा है कि यह सुविधा केवल घरेलू उपभोक्ताओं को दी जाएगी। चुनाव से पहले इसे नीतीश कुमार का मास्टरस्ट्रोक माना जा रहा है।

बिहार सरकार ने हर परिवार को 100 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने की योजना तैयार की है। ऊर्जा विभाग के प्रस्ताव को वित्त विभाग से मंजूरी मिल गई है। उम्मीद है कि जल्द ही यह प्रस्ताव कैबिनेट के समक्ष लाया जाएगा। इस चुनावी साल में नीतीश सरकार बिहार के बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत देने की तैयारी में है। राज्य सरकार 100 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने की योजना पर विचार कर रही है, जिसका सीधा फायदा लाखों परिवारों को होगा। इससे उपभोक्ताओं को हर महीने सैकड़ों रुपये की बचत होगी और उनकी जेब पर महंगाई का बोझ भी कम होगा। इस योजना पर अंतिम फैसला कैबिनेट की बैठक में लिया जाएगा। अगर इस योजना को मंजूरी मिल जाती है, तो जल्द ही राज्य में इसकी घोषणा की जा सकती है। माना जा रहा है कि इस योजना से उन गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों को बड़ी राहत मिलेगी, जिन्हें हर महीने बिजली का बिल चुकाना मुश्किल होता है। उल्लेखनीय है कि बिहार में 2025 में विधानसभा चुनाव होने हैं और राजनीतिक दलों ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं।

नक्सल प्रभावित झारखंड में मिली सुरक्षाबलों को बड़ी कामयाबी, माओवादियों के पांच बंकर ध्वस्त, दो आईईडी बरामद

नई दिल्ली, एजेंसी। सुरक्षा बलों ने एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए चाईबासा के जराईकेले थाना क्षेत्र के कल्पबुरू के जंगलों में माओवादियों के पाँच भूमिगत बंकरों को ध्वस्त कर दिया। ऐसा माना जा रहा है कि भाकपा-माओवादी से जुड़े ये विद्रोही विध्वंसक गतिविधियों को अंजाम देने के बाद छिपने के लिए इन बंकरों का इस्तेमाल करते थे। पुलिस ने बताया कि सुरक्षा बलों ने पश्चिमी सिंहभूम जिले के एक वन क्षेत्र में माओवादियों के पाँच बंकर ध्वस्त कर दिए और उनके द्वारा लगाए गए दो इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस (आईईडी) बरामद किए। एसपी राकेश रंजन ने एक बयान में बताया कि सुरक्षा बलों की एक संयुक्त टीम ने खुफिया जानकारी मिलने के बाद तलाशी अभियान शुरू किया था कि माओवादियों ने छोटानागरा इलाके के जंगलों में चल रहे नक्सल विरोधी अभियानों को बाधित करने के लिए बड़ी मात्रा में विस्फोटक छिपाए हैं। उन्होंने कहा, 'शुक्रवार को अभियान के दौरान, सुरक्षाकर्मियों ने दो आईईडी बरामद किए और माओवादियों के पाँच बंकर ध्वस्त कर दिए।' एसपी ने बताया कि टीम ने बंकरों से डेटोनेटर और तीर बम सहित अन्य सामान भी बरामद किया।

उच्च न्यायालय ने कथित कॉपीराइट उल्लंघन पर कुकू एफएम को नयी कड़ी के प्रसारण से रोका

नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने कथित कॉपीराइट और ट्रेडमार्क उल्लंघन को लेकर ऑडियो प्लेटफॉर्म 'कुकू एफएम' को एक खास ऑडियो शृंखला की नयी कड़ी प्रसारित करने से रोक दिया है।

न्यायमूर्ति सौरभ बनर्जी ने प्रतिद्वंद्वी ऑडियो प्लेटफॉर्म 'पॉकेट एफएम' द्वारा दायर एक याचिका पर यह आदेश सुनाया। याचिका में आरोप लगाया गया था कि प्रतिवादी शो के शीर्षक, पात्र, पोस्टर और संपूर्ण कहानी सहित इसकी मूल सामग्री की ''थोक और व्यवस्थित नकल'' में लगा हुआ था।

अदालत ने 10 जुलाई के आदेश में 'कुकू एफएम' को विवादित शो की कोई भी आगे की कड़ी जारी नहीं करने और विचाराधीन सामग्री से संबंधित विवरण प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। याचिका में 'कुकू एफएम' पर अनधिकृत नकल के 30 से अधिक मामलों का आरोप लगाते हुए इससे लगभग 80 करोड़ रुपये का हर्जाना भी मांगा गया है।

'दोनों इंजनों का फेल होना गंभीर बात', एएआईबी रिपोर्ट पर पूर्व एयर मार्शल संजीव कपूर ने उठाए सवाल

नई दिल्ली, एजेंसी। अहमदाबाद में हुए एअर इंडिया की फ्लाइट AI 171 के दर्दनाक हादसे की प्रारंभिक रिपोर्ट सामने आने के बाद अब सेवानिवृत्त एयर मार्शल संजीव कपूर ने इस पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि रिपोर्ट में अभी भी कई संदेह और सवाल बने हुए हैं। उन्होंने कहा कि जो प्रारंभिक रिपोर्ट सामने आई है, वह पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है। मेरे मन में कई संदेह हैं।

सबसे बड़ा सवाल यह है कि दोनों इंजन कैसे फेल हो गए?उन्होंने कहा कि हादसे से पहले विमान से 'मेडे कॉल' दी गई थी, जो पायलट तभी देता है जब स्थिति बहुत गंभीर और जानलेवा हो। उन्होंने कहा कि इसके अलावा रिपोर्ट में राम एयर टर्बाइन (आरएटी) के एक्टिवेट होने का जिक्र है, जो संकेत देता है कि दोनों इंजन और इलेक्ट्रिक सिस्टम पूरी तरह फेल हो चुके थे।

पायलट्स ने इंजन दोबारा चालू करने की कोशिश की

संजीव कपूर ने बताया कि बोइंग 787 विमान के मैनुअल के अनुसार, अगर दोनों इंजन बंद हो जाएं तो उन्हें दोबारा चालू करने के लिए लीवर को हाथ से दोबारा चालू (मूव) करना पड़ता है। उन्होंने कहा कि मेरी समझ के मुताबिक, टेकऑफ के तुरंत बाद ही दोनों इंजन फेल हो गए। पायलट्स ने 'मेडे' कॉल दी और इस थोड़े से समय में उन्होंने इंजन को दोबारा स्टार्ट करने की कोशिश भी की।

हादसे पर संदेह बरकरार

इसके साथ ही एयर मार्शल ने साफ किया कि जब तक पूरी जांच और अंतिम रिपोर्ट नहीं आ जाती, तब तक यह कहना मुश्किल है कि वास्तव में क्या हुआ। लेकिन उन्होंने यह भी जोड़ा कि एक ही समय पर दोनों इंजन फेल होना बेहद असामान्य है और इसकी गंभीरता से जांच होनी चाहिए। गौरतलब है कि यह हादसा 12 जून को हुआ था, जब अहमदाबाद से लंदन जाने वाली एअर इंडिया की फ्लाइट AI 171 टेकऑफ के कुछ सेकंड के भीतर दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी। इस भयावह हादसे में 260 लोगों की जान चली गई थी। इस हादसे के एक महीने के बाद शनिवार को एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो (एएआईबी) ने इस पर एक 15 पन्नों की प्रारंभिक रिपोर्ट जारी की है।

भोजपुरी एक्ट्रेस आकांक्षा पुरी ने पिंक ड्रेस में ढाया कहर, इंस्टाग्राम पर शेयर की हॉट तस्वीरें

भोजपुरी और टीवी एक्ट्रेस आकांक्षा पुरी ने अपने लेटेस्ट फोटोशूट से सोशल मीडिया का तापमान बढ़ा दिया है। आकांक्षा ने पिंक कलर की खूबसूरत लेस ड्रेस पहनकर अपनी कुछ हॉट तस्वीरें इंस्टाग्राम पर शेयर की हैं, जिनमें उनका बोल्ड और ग्लैमरस अंदाज देखते ही बनता है। एक्ट्रेस ने पोस्ट में लिखा, गुलाबी रंग के हर टांके में रोमांस। फोटोज में आकांक्षा का कॉन्फिडेंट पोज, सॉफ्ट कर्ल हेयरस्टाइल और मिनिमल मेकअप उनके लुक को और भी एलिगेंट बना रहा है। पिंक ड्रेस के साथ मैचिंग नेल पॉलिश और ओपन हेयर ने भी उनके ग्लैम लुक में चार चांद लगा दिए हैं। फैंस उनकी इन तस्वीरों पर दिल खोलकर प्यार लुटा रहे हैं और कमेंट सेक्शन में फायर और हार्ट इमोजी की बारिश कर रहे हैं।

कुछ ही घंटों में इन तस्वीरों को हजारों लाइक्स मिल चुके हैं। सोशल मीडिया पर यूजर्स ने उन्हें फैंटास्टिक, ब्यूटीफुल और स्टनिंग बताते हुए तारीफों के पुल बांधे हैं। आकांक्षा पुरी का यह लेटेस्ट फोटोशूट एक बार फिर साबित करता है कि वह सिर्फ एक शानदार एक्ट्रेस ही नहीं बल्कि एक फैशन दीवा भी हैं, जिनका हर लुक सोशल मीडिया पर छा जाता है।

आकांक्षा पुरी का ये अंदाज यह भी दिखाता है कि वह अपने फैशन सेंस से हर बार फैंस को सरप्राइज करना जानती हैं। उनके हर लुक में एक खास कॉन्फिडेंस और स्टाइल नजर आता है, जो उन्हें बाकी से अलग बनाता है और यही वजह है कि उनकी हर तस्वीर इंटरनेट पर वायरल हो जाती है।

सैफ पर हमले के बाद करीना कपूर की कार पर भी हुआ था अटैक, रोनित रॉय ने किया चौंकाने वाला खुलासा

हाल ही में अभिनेता रोनित रॉय ने खुलासा किया कि सैफ अली खान पर चाकू से हमला होने के बाद करीना कपूर खान पर भी अटैक हुआ था। आइए जानते हैं पूरी बात।

टीवी और फिल्मों की दुनिया के मशहूर अभिनेता रोनित रॉय ने एक हैरान कर देने वाली जानकारी साझा की है। अभिनेता ने बताया कि एक्टर सैफ अली खान पर चाकू से हमला होने के बाद करीना कपूर खान की गाड़ी पर भी हमला किया गया था, जिसने अभिनेत्री को बहुत डरा दिया था। हालांकि, एक्ट्रेस से जुड़ी यह घटना गंभीर नहीं थी, लेकिन इसने उन्हें झकझोर कर रख दिया था। चलिए जानते हैं अभिनेता रोनित रॉय ने क्या बताया।

करीना कपूर की कार पर हुआ था हमला

अभिनेता रोनित रॉय हिंदी रश के साथ एक इंटरव्यू में शामिल हए। बातचीत के दौरान एक्टर ने बॉलीवुड अभिनेता सैफ अली खान पर हुए हमले का जिक्र किया। उन्होंने बताया, 'सैफ अली खान को अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद, जब करीना कपूर घर लौट रही थी। तो उसी दौरान करीना की कार को धक्का दिया गया, जिस कारण वह घबरा गई थीं फिर उन्होंने मुझसे सैफ को घर ले जाने के लिए कहा।'

मीडिया वाले भी थे तैनात

आगे बातचीत में रोनित रॉय ने बताया कि करीना कपूर के साथ हुई उस घटना के दौरान मीडिया भी आसपास थी और लोग बहुत करीब आ गए थे। अभिनेत्री के कहने के बाद रोनित रॉय, सैफ अली खान को घर लेकर गए। हालांकि, उन्होंने बताया कि जब वह घर पहुंचे, तो सुरक्षा पहले से ही तैनात थी और उन्हें पुलिस बल का भी पूरा समर्थन मिला।

कब हुआ था सैफ अली खान पर हमला?

16 जनवरी 2025 को एक हमलावर सैफ अली खान के बांद्रा स्थित घर में घुस आया था। फिर जब अभिनेता अपने छोटे बेटे जेह को उस घुसपैठिए से बचाने की कोशिश कर रहे थे, तो हमलावर ने एक्टर पर चाकू से वार कर दिया था, जिससे अभिनेता घायल हो गए थे। हालांकि, बाद में पुलिस ने घुसपैठिए को पकड़ लिया था।

स्वामी, प्रकाशक व मुद्रक प्रभात पांडेय द्वारा साई ऑफसेट प्रिंटर्स 40, वासुदेव भवन कैसरबाग, लखनऊ (उत्तर प्रदेश) से मुद्रित एवं 2/74, विक्रांत खंड, गोमती नगर, लखनऊ से प्रकाशित।
शाखा कार्यालय: S-15/109, सेक्टर -15, इंदिरा नगर, लखनऊ। समस्त लेख, रचनाओं एवं विज्ञापन में लेखन और विज्ञापनदाताओं के अपने विचार हैं। इसके लिए आर्यावर्त क्रांति की कोई जिम्मेदारी नहीं है। किसी भी विवाद की स्थिति में न्याय क्षेत्र लखनऊ, उत्तर प्रदेश ही होगा। RNI No: UPHIN/2014/57034 Website: aryavartkranti.com
*सम्पादक: प्रभात पांडेय सम्पर्क: 9839909595, 8765295384 Email: aryavartkrantidainik@gmail.com